साप्ताहिक

पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

समय माया

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार

Website: www.samaymaya.com
Email: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

Cell: +91 9300755803, 9425125569
Phone Fax: +91 731 2530859

(C) All Copyrights reserved with chief editor, do not publish any matter without prior written permission

In case of any dispute, may be solved only in Indore Court Jurisdiction

वर्ष 7 अंक 13 प्रति सोमवार इंदौर, 5 नवंबर से 11 नवंबर 2012 पृष्ठ 8 मूल्य 2/- रुपए

धूर्तों को कमीशन दो देश और हर व्यवस्था बेचने व गिरवी को तैयार

पेंशन, बीमे व्यवसाय में क्या जरूरत है, विदेशी निवेश की

करोड़ों पेंशनर्स को भूख से तड़पा-तड़पा कर मारेंगे, धन आते ही डुबाकर ले जाएंगे

कांग्रेस और उनके सहयोगी संप्रग के सहयोगी डकैतों को बस कमीशन बांटते चलो और पूरे देश की व्यवस्था को अपनी कमाई के हिसाब से बांटते और ताश के पत्तों की तरह फेंटते रहे, फिर चाहे राष्ट्र की 125 करोड़ भूखी मरे। बेरोजगार हो, परमाणु निकिरण से घिर कर मरे। उसकी अपनी कमाई विदेशी लूटकर पैंशन निधि के रूप में कब्जे को लेकर भाग जाएं, उनकी बला से। उन्हें तो तत्काल धन दे दो। वो रिजर्व बैंक को ठेके पर दे देंगे। इन धूर्त शूकरों को तो धन देते चलो जो चाहिए बोलो।

यूरोपियन एजेंट सोनिया का बार-बार अमेरिका जाना और कैंसर का बहाना बनाना। कैंसर पीड़ित व्यक्तियों से पूछो कैंसर क्या होता है। उसकी पीड़ा न केवल चेहरे पर बल्कि शरीर भाषित कर देता है और कैंसर चार दिन में ठीक नहीं हो जाता। यह तो उस युरोपियन एजेंट की चाल थी ताकि एक तरफ मीडिया और जनता सहानुभूति बटोर सके तो दूसरी तरफ लोकसभा में बहस के वक्त अपने कमीशनखोरी और अपने युरोपियन व अमेरिकन आकाओं की जी हुजूरी को मजबूरी चेहरे से न झलक जाए।

जब-जब वो अमेरिका से कैंसर के बहाने मौज मस्ती और अपने आका का हुकुम बजाकर लौटी, तब-तब राष्ट्र के सबसे हरामखोर, कमीनशखोर, धूर्त प्रधानमंत्री मनमोहन ने विदेशी कम्पनी के हितों में फैसले लेकर विदेशियों के कमाई के रास्ते खोले राष्ट्र की सम्पत्ति और जनता को अपने बाप की सम्पत्तिमान एक तरफ तो विश्व बैंक से एशियन विकास बैंक से कर्ज लेकर 10 से 25 प्रतिशत धन डकार लिया जाता है तो दूसरी तरफ हर कदम उससे जुड़ी हर वस्तुओं सेवाओं, यशा, बीमा, सड़कें, बिजली, पानी, शेयर बाजार, खुदरा बाजार आदि को विदेशियों को लूटने रणने और मुनाफे के लिए छोड़ देते हैं। ये है महान अर्थ शास्त्री, भूतपूर्व भारतीय रिजर्व बैंक के राज्यपाल हमारे देश के महा जालसाज महा मक्कार हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, देश की जनता इनके लिए कीड़े-मकोड़े से ज्यादा कुछ नहीं, जिसने सत्ता में आते ही जनता के ऊपर विदेशी दवा कम्पनियां बनाई औषधियों के परीक्षण के लिए 125 करोड़ मानकों को जानवर मानकर कभी भी कहीं भी किसी पर भी हर अस्पताल के बिना करोड़ों के बताए, कैसी भी कोई भी दवा का परीक्षण करने की खुली छूट दे दी, जो सबसे पहले चूहों, शूकरों, खरगोशों, बंदरों पर परीक्षण करनी चाहिए थी, अब सीधे मानक रूपी पर परीक्षण की जा रही है तो ड्रग ट्रायल का ही शिकार होते हैं। फिर भी डॉक्टर रूप गिद्धों को कई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने बच्चों, व्यस्कों या बुजुर्गों में किससे लाखों रुपए वसूलने के बाद भी उसकी हत्या कर मौत दी। न स्वास्थ्य विभाग को, न स्वास्थ्य मंत्री को न मुख्यमंत्री पर प्रधानमंत्री सब चुप हैं। (शेष पेज 7 पर)

अमेरिका की जनता न चुने पुनः ओबामा को

ओबामा, हिलेरी से रोमांस करे, नहीं चलाये सत्ता

अमेरिकी अर्थव्यवस्था चौपट, बेरोजगारी, ऋण बढ़ा, साख गिरी

वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा के सत्ता संभालने के बाद चारों तरफ मुंह की खाई,ल क्योंकि उन्हें पत्नी मिशेल और दो लड़कियों के बाद भी देश में और देश के बाहर अपनी विदेश सचिव हिलेरी क्लिंटन से रोमांस के चलते राष्ट्र और राष्ट्र के बाहर समस्याओं को देखने, समझने और सुलझाने के लिये समय ही नहीं मिल पाया, ताकि वो राष्ट्र की समस्याओं की तरफ ध्यान देते, प्रकृति ने सभी को 24 घंटे बराबरी से दिये हैं। उसमें चाहे आप रोमांस कर लो, आराम कर लो, मौज-मस्ती में समय व्यतीत कर लो। समय तो गुजर ही जायेगा। अब अमेरिकी राष्ट्रपति भी प्रकृति के इस सिद्धांत के शिकार हो गये, बचे हुए समय में भारत और चीन को कोसते रहे, कि ये सारी नौकरियां ले जाते हैं। आउटसोर्सिंग बंद करवा दी, क्यों भाई अमेरिकीयों तुम्हारा ही उद्देश्य था कि विश्व व्यापार संगठन में कोई कहीं भी व्यापार कर सकता हैं, तो अब भारत, चीन और अन्य एशियाई देशों को क्यों कोस रहे हो, यथार्थ यह है कि तुम्हें हिलेरी से रोमांस करने से, बहुराष्ट्रीय कं. से मोटा कमीशन डकार कर उनकी कठपुतली बन नाचने, जालसाजी पूर्ण कृत्यों दूसरे देशों यथा ईरान के पेट्रोल पर कब्जा करने के मंसूबे बांधने, फर्जी मुठभेड़ में नकली ओसामा का मारने, जनता और मीडिया का ध्यान बंटाने के लिये मंगल पर जाने के झूठे षड्यंत्रों से, झूठी आन-बान-शान में जीने और जनता को ख्वाब दिखाने से फुर्सत मिले तो बेरोजगारों के लिये लघु और कुटीर उद्योगों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था करते,

(शेष पृष्ठ 7 पर)

कैसा जनहित? स्वहित पहले देखता है शिवराज

हर कदम दो मुंहा-कथनी कुछ, करनी कुछ

निवेशक आयोजन की आड़ में अपने कालेधन के विनियोजन और कमाई की व्यवस्था

म.प्र. का मुख्यमंत्री शिवराज नाम शिव काम दानवों को हरकदम दो मुंही नीति अपनाता रहा है, पूरे देश में जहां बांध बने 40-50 वर्ष गुजर जाने के बाद भी विस्थितियों का पुनर्वास न केन्द्र सरकार कर सकी, न राज्य सरकारें, सर्वोच्च न्यायालय के अनेकों आदेशों के बाद भी सारे सत्ताधीशों केवल आश्वासनों के पुलिंदें थमाते रहे हैं। विस्थितियों और पीड़ितों पर बड़ा-बड़ी लम्बी-चौड़े बयान देने वाले इस राक्षक ने तो उन पर लट्ठ भी बरस गए और पुलिस से मारापीटी भी करवाई।

आखिर ये बताए कि इंदिरा सागर से म.प्र. को क्या मिला लाखों-करोड़ों खर्च करने के बाद अभी भी दायी और बायी बैंक नहर का कार्य स्तर ही और अधूरा है जो सन् 2000 में पूरा हो जाना चाहिए था, उसके बाद में पुनः जब भराव में लाखों हेक्टेयर जमीन डूबी और लाखों लोगों को विस्थापन झेलना पड़ा और अभी भी विस्थापितों काम तो पूरा मुआवजा मिला न ही उनके पुनर्वास की उचित व्यवस्था

की गई, पर न्यायालयों में हर कदम झूठे हलफनामें अवश्य पेश किए गए और कार्यश्रमी तक हल नहीं हो सका है। ओंकारेश्वर और हरदा के गांवों में विस्थापितों ने जब पानी में खड़ा होकर आंदोलन किया तो हरदा जाकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने उन पर और लट्ठ बरसवा दिए। ये हैं हमारे मुख्यमंत्री गरीबों, बेसहारा, हरिजन आदिवासियों की नीति, उनके नाम पर अरबों रुपए प्रति वर्ष हजम कर लिए जाते हैं।

इस तारतम्य में एक तरफ भू-माफियाओं, खनन माफियाओं को छोड़ने के भाषण दिया जाता है, दूसरी तरफ उनके ही मंत्री पूरे प्रदेश में खनन माफियाओं को पालते-पोसते रहकर अपना हिस्सा बटोरते हैं। जबकि जो पुराना खनन माफिया था, उसे ही खनन एवं खनिज मंत्री पद राजेन्द्र शुक्ला को दे दिया गया जो प्रतिवर्ष रुपिए 10000 करोड़ से अवैध उत्खनन करवाता है। अपने भाषणों और सरकारी विज्ञापनों में मु.मं. शिवराज पर्यावरण को बचाओ अवैध उत्खनन नहीं होने दिया जाएगा जबकि अकेले इंदौर में ही लो.नि.वि. और रा.रा. प्राधिकरण के ठेकेदारों भवन निर्माण ठेकेदारों ने पड़ाव के पहाड़ धार, नेमावर, उज्जैन मार्ग पर, सेंधवा, महू मार्ग, देवास की पहाड़ियों को जो भोपाल मार्ग, शाजापुर, हाटपीपल्या मार्ग पर है, ठेकेदारों और खनन माफिया ने इसे गिट्टी पत्थर आधार तक न केवल नोंच और काट मारा और न ही शासन को रॉयल्टी मिली।

म.प्र. में अकेले रा.रा. मार्ग प्राधि. और म.प्र. रोड डकैत कार्यो. की बीओति की 7000 किमी सड़कों में ही रा.रा. मार्ग प्राधि. और स.वि.नि. के ठेकेदारों ने ही एकहरे, दोहरे, (शेष पेज 6 पर)

पूरा शहर फिर खुदेगा मेट्रो प्रोजेक्ट में

पहले बी.आर.टी.एस. में आगे मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट में

बीआरटीएस पूरा होना था 2008 में, मेट्रो पूरा नहीं होगा 2030 तक

भारत भूमि का अनादिकाल से यह दुर्भाग्य रहा है कि सब कुछ श्रेष्ठ होने यथा स्थिर और निश्चित जलवायु, उर्वरा कृषि भूमि, महत्वपूर्ण खनिजों से भरी-पूरी, वर्षभर बहने वाली नदियां, पहाड़ों, मानव तन-मन को आह्लादित करने की सभी सुविधायें, शास्त्रों में वर्णितानुसार देवताओं की प्रिय भूमि स्वाभाविक था दानवों की भी प्रिय, फिर मानवों में तो देवों और दानवों की सभी प्रवृत्तियों से ओतप्रोत रहा है, फिर मानव को जितनी सुविधायें, अधिकार संपन्न हुआ वो उतना ही घोर स्वार्थी और मक्कार हुआ, वर्तमान भारत में भी जनता और सत्ताधीशों में हर कदम घोर स्वार्थ परता का चारों तरफ साम्राज्य हैं।

सत्ताधीशों के सत्ता और अधिकार मिलते ही वह दानव बन दूसरे के हकों का बलात्कार कर अपनी स्वार्थसिद्धि और अपनी लिप्सा को पूरा करने वो जन हितों का दिखावा करता है, यह दानवीय मानसिकता ही इस भारत भूमि का

अनादि से अनंत तक घोर अभिशाप रही है और अनंत भविष्य तक रहेगी। यह दृष्टांत केन्द्र के हर विभाग जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के कार्यालय से लेकर गांवों की पंचायतों, जनपद पंचायतों, नगर पालिकाओं, परिषदों और नगर निगमों तक का सर्वमान्य सत्य है, इसकी सत्यता का आंकलन हर व्यक्ति, हर कार्यालय में हर कर्मचारी अधिकारी के साथ कर सकता है। इन अधिकारियों-कर्मचारियों की अगर स्वार्थ सिद्धि न हो तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा व्यक्ति जो आम जनता की इकाई है, कितना हैरान-परेशान होगा, वह जितना परेशान-हैरान होगा उल्टे ही उतनी मोटी वसूली होगी। इसके उदाहरण में बीआरटीएस को ही लें, रु. 868 करोड़ की इस परियोजना का क्या हाल हो रहा है। अनेकों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों घायल हो चुके हैं। (शेष पेज 6 पर)

साप्ताहिक समय माया

संपादकीय

लोकतंत्र पूंजीवाद का राक्षस तंत्र

लोकतंत्र में लोक के चुने हुये प्रतिनिधि सत्ता संचालित करते हैं। ताकि सबको सत्ता संचालन में भागीदारी मिले और जनता के मस्तिष्क में कुंठा न पनपे, उसका भविष्य सुखी और समृद्धिपूर्ण हो, राज्य में सत्ताधीश स्वयंभू बन कर जनता का शोषण कर सके, जनता स्वयं अपना मत देकर अपने प्रतिनिधियों को चुनकर सत्ता संचालन करते हुए जनता का भविष्य संवारे, यह लोकतांत्रिक मान्यता विश्व भर में ध्वस्त हो चुकी है। वर्तमान में जनता इस लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जिसे भी सत्ता का तिलक करती है। वह उसी समय से जनहित भूलकर केवल अपना भविष्य देखते हैं। उन्हें जनता के भविष्य से कदापि कोई मतलब नहीं वरन अपनी सत्ता के भविष्य को संवारकर केवल उन्हें अपना बैंक बैलेंस का भविष्य संवारने की चिंता लगी रहती है, उनका भविष्य कैसे सुदृढ़ हों, इसलिए फिर तो पूंजीपतियों और उद्योगपतियों की कठपुतली बन जन और जन के धन, राष्ट्र या जहां की सत्ता के सत्ताधीश होते हैं। वहां के शोषण की व्यवस्था में लगकर राक्षसी वृत्तियों की सार्थकता सिद्ध करते हैं।

इंदौर में संपन्न हो रहे निवेशक सभा का आयोजन इसका उदाहरण है। पूंजीपतियों और उद्योगपतियों की सभा का आयोजन जनहित तो कदापि नहीं, क्योंकि हर निवेशक को अपना पैर जमाने के लिये भूमि चाहिये और भूमि कोई रबर या कागज तो नहीं जितना चाहो जब खींच लो या मशीन में जनता की लुगदी डालकर खींचकर बना लो, इन पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को जो भूमि चाहिये वह कृषि भूमि कृषकों से ओने-पौने में छुड़ाकर ही इन उद्योगपतियों को दी जायेगी, उनको बिजली चाहिए, इंदिरा सागर, सरदार सरोवर, ओंकारेश्वर, मंडलेश्वर में लाखों एकड़ जमीन बांधों में डुबो दी गई, कृषकों को बेरोजगार कर उनकी घर और जमीनें डुबो दी गई। वर्षों बाद भी विस्थापितों को न्याय नहीं मिला, जमीन नहीं मिली जब हरदा में उन्होंने आंदोलन किया तो सत्ताधीशों ने पूंजीपतियों के हितों को संवारने के लिये राक्षसों ने लट्ठ बरसवा दिये।

भारतीय लोकतंत्र में सत्ताधीशों को अपना काला धन निवेशित करने के लिये भी सुरक्षित स्थान चाहिये, भारतीय बैंकों में कितना और कहां रखें, लोग जानकारी निकाल लेते हैं। स्वीट्जरलैंड की बैंकर्स भी जानकारी देने लगे हैं। कितने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज खोलकर धन निवेशित कर लोगों की जुबान पर सच आ ही जाता है। हजारों एकड़ जमीन में, हजारों टैक्सियों, बसों, ट्रकों में, बीओटी सड़कों में, पुलों में निवेशित करें, यथार्थ प्रगट हो ही जाता है, इसलिए बेहतर हैं लोकतंत्र को सत्ताधीश राक्षस, पूंजीपतियों और उद्योगपति राक्षसों के साथ मिलकर जनता का जन-धन की सार्वजनिक संपत्तियों का चंद लोगों के हित में शोषण करते हुए उद्योगों में निवेश करें, उन्हें जन धन से खरीदी गई सस्ती बिजली, पानी, जमीनें उपलब्ध करवाकर अपना और उनका और अपना धन देकर उद्योग खड़े करवाये। सस्तों श्रमिकों का उपयोग कर धन को दूना-चौगुना करें और स्वयं का और सत्ताधीश राक्षसों का भविष्य सुरक्षित करें,

सत्ताधीश राक्षसों और डकैतों की फौज पूंजीपतियों के पोषण और जनता के शोषण के लिये पूंजीपतियों के टुकड़े खाकर कानूनों को बनाने पूंजीपतियों के द्वारा जनता के शोषण के लिये उन्हें संरक्षित करने और उसमें अपना हिस्सा डकारने के लिये बेखबर होकर सोती है। जैसे भारत में क्या टाटा, रिलायंस, आइडिया, वोडाफोन, भारती एयरटेल, बीएसएनएल जनता को दी जाने वाली सेवाओं में प्रतिदिन रु. हजार करोड़ की लूट करती हैं। परन्तु उनके शोषण रोकने के लिये संचार मंत्रालय के मंत्री से लेकर सभी अधिकारियों की फौज ने कानून नहीं बनाये, परन्तु पूंजीपतियों और उद्योगपतियों द्वारा जनता के शोषण के लिये अवश्य टुकड़खोरी से मोटा धन हजम करने के लिये अवश्य कोई न कोई कानून बना कर सत्ताधीश राक्षस जनता को निचोड़ने को कानून अवश्य बनाते रहे हैं। जैसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, भूमि अधिनियमों में परिवर्तन कर कृषकों से भूमि छीनने, डुबोने के लिये जरूर परिवर्तन किये जाते रहते हैं। इसके परिणामस्वरूप शहरों में और गांवों में भूमाफियाओं ने, सरकार ने हजम कर ली। सत्ताधीश राक्षसों ने पूंजीपति राक्षस के साथ मिलकर लोकतंत्र और जनता को तिल-तिल मारने की व्यवस्था अवश्य कर दी, इसमें मनमोहन हो या शिवराज।

म.प्र. श्रम विभाग- वसूली, भ्रष्टाचारी निरीक्षकों और अधिकारियों का अड्डा

श्रम कानूनों का पालन नहीं होता राज्य सरकार के कार्यालयों में

मनोरंजन गृह, पुस्तकालय, कैंटीन की व्यवस्था कहीं नहीं, कार्पोरेट बनाने में अरबों बर्बाद

म.प्र. सरकार के कार्यालयों में ही श्रम कानूनों का पालन नहीं किया जाता। पूरे म.प्र. के कार्यालयों में और न ही निकम्मों, भ्रष्ट निरीक्षकों से लेकर श्रमायुक्त और श्रम मंत्री तक, श्रमिक कानूनों का पालन करवाने के लिये इस विभाग ने कभी अपनी ही सरकार के 100 से ज्यादा विभागों में इन श्रम कानूनों के उल्लंघन और उनके पालन के लिये विभागों के मंत्री से लेकर मुख्य सचिव, अपर सचिवों, प्रधान सचिवों, सचिवों, आयुक्तों संचालकों से लेकर जिलाधीशों और जिलाधिकारियों को कहा या लिखा गया।

भारतीय कारखाना अधि. 1948 जो कि 10 कर्मचारियों, जिसमें अधिकारी, कर्मचारी सभी शामिल हैं जो कि शक्ति, यथा विद्युत शक्ति, जल, कोयले, डीजल पेट्रोल से शक्ति उत्पन्न कर कार्य करते हैं। कारखाना अधि. 1948 की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं व अन्य श्रम कानूनों में स्पष्ट लिखा गया है कि श्रमिकों, कर्मचारियों के साढ़े चार घंटे काम करने के बाद भोजनावकाश होगा, जिसमें साथ ही कर्मचारियों के मनोरंजन हेतु आंतरिक खेतों यथा शतरंज, टेनिस, बेडमिंटन, ज्ञानवर्धन हेतु समाचार पत्र, पत्रिकायें, पुस्तकों हेतु पुस्तकालय की व्यवस्था नियोक्ता अर्थात शासन द्वारा की जानी चाहिये।

कर्मचारियों को भोजनावकाश काल में भोजन, चाय-दूध आदि के लिये भोजनालय, स्वल्पाहार गृह आदि की व्यवस्था नियोक्ता को करनी चाहिये जिसमें आधी कीमतों पर गर्म चाय, दूध, नाश्ते से लेकर ताजे भोजन तक की व्यवस्था नियोक्ता अर्थात शासन को करनी चाहिये आधी कीमत कर्मचारी देगा और आधी कीमत का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जायेगा, यह स्पष्ट व्याख्या कानूनों में होने के बाद भी, म.प्र. शासन का वल्लभ भवन, सतपुड़ा, विंध्याचल से लेकर जिलों, तहसीलों तक के किसी भी विभाग इन श्रमिक कानूनों का पालन कभी और कहीं नहीं किया जाता। निःसंदेह बड़े शासकीय भवनों के आसपास इंडियन काफी हाउस की व्यवस्थायें तो कहीं-कहीं पर हैं। परन्तु इंडियन काफी हाउस के केरलीयन सहकारी संघ भारी महंगी कीमतों पर, चाय-दूध, काफी, डोसा, इडली, भोजन आदि बेचता है। इस कारण ऐसे कार्यालयों के बाहर लगे ठेलों पर लोग पूरी कीमतें चुका कर चाय-काफी और नाश्ता करना बेहतर समझते हैं।

विश्व व्यापार संगठन, बहुराष्ट्रीय कं. के दबाव के चलते केन्द्र और राज्यों की सरकारें अपने कार्यालयों को अरबों रु. खर्च कर जिसका 50% पैसा उस विभाग के कर्मचारी अधिकारी डकार गये कार्पोरेट कल्चर में ढालने में लगे हैं। जहां पहले पत्थर की पट्टीयां लगी थी। बिना ढंग से भवन की नीचे भराई, सुधार, रंगाई-पुताई किये फर्श पर नीचे ग्लेज्ड टाइल्स लगा दी गई हैं। सबसे ज्यादा पैसा पिछले 5 वर्षों में लो.नि.वि. के मुख्य अभियंता कार्यालय, अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्रीयों, 34 खण्डों में खर्च किया गया। इंदौर, उज्जैन, अंचल के जो कार्यालयों में देखा गया, वही हाल लोक स्वा. यंत्री के मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्री कार्यालयों इंदौर-उज्जैन कार्यपालन यंत्रियों, उपखंडों में जिस तरह से जनधन को सौन्दर्य और कार्पोरेट, कल्चर विकसित करने के नाम पर बर्बाद किया जा रहा हैं, वैसे तो सभी शासकीय कार्योलयों में हर जिले में करोड़ों की बर्बादी की गई और की जा रही है, स्वाभाविक है, आधा अंदर आधे का कार्य संपन्न इतना घटिया किस्म का हो रहा हैं, जो 6 माह साल भर में ही तो टाइल्स उखड़ने लगी है। यह काम देवास के उद्यानिकी, कृषि, शिक्षा, चिकित्सा विभाग में देखा जा सकता है।

पूरे म.प्र. में शायद कार्पोरेट विकसित करने के नाम पर हर विभाग के धन को एकत्र किया जाये तो रु. 1000 करोड़ से ज्यादा बर्बाद किया गया, इसके दूसरी ओर किसी भी राज्य सरकार के कार्यालय और कार्यालय में मनोरंजन कक्ष, कैंटीन, पुस्तकालय आदि की कानून संभव व्यवस्था नहीं की गयी, जो कार्पोरेट कल्चर विकसित करने की पहली सीढ़ी थी।

जबकि श्रम कानूनों में कर्मचारियों-अधिकारियों को इस मनोरंजन, पुस्तकालय, कैंटीन आदि की व्यवस्था का उद्देश्य था कि कर्मचारियों और अधिकारियों को हर साढ़े चार-पांच घंटे के अंतराल के बाद पुनः तरोताजा कर मस्तिष्क को और ताजगी प्रदान कर बेहतर क्षमताओं से बेहतर कार्यक्षमता विकसित करना था, जिसका लाभ न केवल कर्मियों को वरन् नियोक्ता को भी खर्च किये धन से कई गुना ज्यादा मिलता हैं, कर्मियों की कार्यक्षमता का दीर्घ अवधि तक लाभ मिलता रहे इसीलिये उसे दो वर्ष में एक बार घर आने जाने का किराया और सवैतनिक अवकाश दिया जाता हैं, 4 वर्ष में 1 बार 3000 कि.मी. की यात्रा का परिवार के साथ घूमने की पात्रता कर्मियों की उनके वेतन की पात्रता के अनुसार दिया जाता है।

केंद्रीय कर्मचारियों और अधिकारियों के हर कार्यालय परिसरों में इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता हैं, बैंक, बीमा आदि की छोटी शाखाओं में भी पुस्तकालय, मनोरंजन का आवंटन आता है, वर्ष में एक बार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। इसके विपरीत जबकि श्रम विभाग राज्य सरकार की सूची का विभाग होने के बाद भी राज्य सरकार के बड़े-बड़े परिसरों से लेकर ब्लाक तहसील स्तर के परिसरों तक में कहीं कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, जबकि इंदौर का जिलाधीश कार्यालय का प्रशासनिक संकुल जहां 20 से ज्यादा विभाग कार्यरत है। न तो कैंटीन की व्यवस्था बनाई गई है, न ही मनोरंजन गृह, पुस्तकालय आदि की पूरे परिसर में कोई व्यवस्था नहीं हैं, जबकि लगभग 500 से ज्यादा कर्मचारी-अधिकारी यहां बैठते हैं। वही हाल चेतक चैंबर में जहां 15 वाणिज्यकर अधिकारियों, सहा. आयुक्तों, उपसंभागायुक्त, 1 अपर आयुक्त के कार्यालय हैं। लगभग 300 से ज्यादा कर्मचारी अधिकारी कार्यरत होने के पश्चात भी पुस्तकालय, मनोरंजन गृह कैंटीन की कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि हर विभाग में इस मद का पैसा हर वर्ष आता है, झूठे बिल-व्हाउचरों से पैसा निकालकर डकार लिया जाता हैं, वही हाल मोती बंगला स्थित संभागायुक्त कार्यालय, वाणिज्य कर आयुक्त कार्यालय और प्रदेश मुख्यालय, श्रमायुक्त कार्यालय और प्रादेशिक मुख्यालय, संचालक, म.प्र. औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का प्रादेशिक मुख्यालय होने के साथ लोकायुक्त कार्यालय, नापतौल, संभागीय कार्यालय जहां अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा मुख्य अभियंता कार्यालय हैं। परन्तु मनोरंजन गृह, पुस्तकालय और केंटीन की राज्य सरकार द्वारा व्यवस्था नहीं की जाती हैं, जो इंडियन काफी हाउस की व्यवस्था है वहां हर पेय व खाद्य वस्तु बाजार दरों से न केवल दुगुनी और व्यावसायिक कीमत पर हैं, वरन अनुदान दरों पर आधी कीमत पर मिलने की जालसाज इस केरेलियन व्यवस्था में कल्पना भी नहीं की जा सकती हैं, कि वे घटी दरों पर खाद्य बेचेंगे। पुलिस जिला मुख्यालयों से लेकर थानों पर निरीक्षकों, पुलिस वालों को हरदम तरोताजा रखने के लिये इस व्यवस्था का होना बहुत जरूरी होता है, ताकि वे हरदम तरोताजा, स्फूर्तिवान रहकर जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने में तनावमुक्त रह सकें, यही कारण है कि तनाव और अवसाद से घिरे पुलिसकर्मी अवसाद के चलते वरिष्ठों पर हमले करने और स्वयं आत्महत्या तक करते रहे हैं। स्वाभाविक है कि जब वे स्वयं शारीरिक और मानसिक रूप से तरोताजा और फिट नहीं तो जनसुरक्षा क्या खाक करेंगे, तनाव मिटाने शराब-कबाब का ही सहारा लेंगे।

पलासिया में वही हाल लोक निर्माण मुख्य अभियंता कार्यालय में न केवल परिसर भी काफी बड़ा है वरन वहां 5 कार्यालय कार्यपालन यंत्रियों के होने के साथ ही मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्री कार्यपालन यंत्रीयों के अलग-अलग कार्यालय होने के उपरान्त भी यहां भी कोई मनोरंजन गृह, कैंटीन, पुस्तकालय की भी व्यवस्था नहीं है, कैंटीन तो दूर की कोढ़ी है, लो.नि. परि. में पूर्व में कार्यरत कर्मचारी श्री पिल्ले ने बताया था कि एक टेनिस की टेबिल हुआ करती थी और पूरा मनोरंजन कक्ष भी हुआ करता था, बाद में 90-95 में बंद कर दिया गया और आवाम का पैसा हजम किया जाने लगा, मूसाखेड़ी में नर्मदा परियोजना का भी बड़ा कार्यालय हैं, जहां दो अधीक्षण यंत्री, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई, कार्यपालन यंत्री व अन्य लो.स्वा. यांत्रि. कार्यालय है। पर यहां भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं पाई जाती, यही हाल इंदौर नगर निगम, उज्जैन नगर पालिका देवास, धार, जबलपुर, सागर, ग्वालियर, भोपाल जैसे निगमों में नहीं है, तो छोटे शहरों, तहसीलों में तो उम्मीद करना ही बेकार हैं, जब म.प्र. का इंदौर स्थित श्रमायुक्त का प्रादेशिक कार्यालय अपने यहां मनोरंजन गृह, पुस्तकालय, कैंटीन की श्रम कानूनों के अंतर्गत व्यवस्था नहीं कर पाया, तो यहां बैठे उपायुक्त, सहायुक्त श्रमाधिकारी, श्रम निरीक्षकों से क्या उम्मीद की जा सकती हैं, जिनका काम ही हर फैक्ट्री, व्यावसायिक संस्थान आदि से रु. 2 हजार 5 हजार तक श्रमिकों की संख्या और आकार के हिसाब से वसूली कर मुटिया रहे हैं।

और पूरे सांवेर मार्ग औद्योगिक क्षेत्र, पोलोग्राउन्ड, लक्ष्मी नगर, पालदा आदि और शहर भर में फैले छोटे-मोटे औद्योगिक संस्थानों से लाखों रु. की वसूली कर, निरीक्षण पंजी में हस्ताक्षर कर चुपचाप सिर झुका कर चल देते हैं। जबकि सभी औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों को विपरीत और विषम परिस्थितियों में काम करने के उपरांत कलेक्टर रेटर की मजदूरी इप्का, प्लेथिको, रेन बेक्सी देवास, पीडीपीएल, नेमावर रोड, लाखानी, सांवेर, लक्ष्मी नगर, देवास रोड, पालदा, पोलोग्राउंड में नहीं मिल रहीं, तो फिर देवास, पीथमपुर, उज्जैन, मंदसौर, भिंड के मालनपुर, भोपाल के मंडीदीप, जबलपुर के आदि के औद्योगिक क्षेत्रों में मिलने की कल्पना भी बेकार हैं, हर जिले में जहां औद्योगिक क्षेत्र है और फैक्ट्रीयां है श्रम निरीक्षक और श्रमाधिकारी महीना वसूली कर श्रमिकों का घोर शोषण करवाते हैं। सुविधायें तो श्रम कानूनों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को ही नहीं दिलवा पाते तो निजी क्षेत्रों की कल्पना भी बेकार हैं।

बातें व भाषणबाजी राष्ट्रहित की सभी काम पार्टी पदाधिकारियों के हित के

किसान संघ का उद्देश्य कृषक हित नहीं, राजनैतिक स्वार्थ सिद्धी

सच्चे राष्ट्रभक्त के. सुदर्शन का स्वदेशी युग समाप्त- गडकरी की विदेशी पूंजी निवेश की वकालत

किसानों को तात्कालिक लाभ पर दीर्घकाल में बंधुआ मजदूर बनने को तैयार रहे

राष्ट्रीय स्वयं संघ के पूर्व सरसंघ संचालक के सुदर्शन जो सच्चे राष्ट्र भक्त थे, उनका देहांत हो गया, समय माया परिवार श्रद्धासुमन अर्पित करता हैं, के. सुदर्शन संघ के एकमात्र ऐसे राष्ट्रभक्त नेता थे जिन्होंने यूरोपीय एजेन्ट सोनिया की सच्चाई को मंच से बयान कर दिया था, जिसके कारण संघ ने उन्हें अलग-थलग भले ही कर दिया था, परन्तु सच्चे राष्ट्रभक्तों के मन में न केवल उनके प्रति वरन् संघ के प्रति भी श्रद्धा जागृत हो गई, कि कम से कम संघ ने एक ही सही ऐसा नेता तो दिया जिसने मंच से इटालियन श्वेतांग का सच उजागरकर दिया, जिसकी आंख से सास स्व. इंदिरा गांधी और पति स्व. राजीव गांधी की मौत पर एक आंसू भी नहीं टपका परन्तु प्रेमी की मौत प झार-झार गंगा-जमुना बहाई थी, वो विदेशी एजेंट थी, है और रहेगी देश को गुलाम बना रही है।

पूर्व सरसंघ संचालक की मृत्यु से संघ में उस स्वदेशी युग का अंत हो गया हैं, अब गडकरी का युग है, जिसे दूसरी बार पुनः भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है, जो स्वयं उद्योगपति तो है हा, साथ ही जिस विदेशी पूंजी निवेश के विरोध में पूरी भाजपा ने लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों में भारत बंद का आह्वान 20 सितम्बर को किया था, उसी के पक्ष में गडकरी ने खुले में विदेशी पूंजी का 51% का निवेश फुटकर व्यवसाय में करने के लिये भी वकालात की, उसके बेटे के नाम से न केवल ताप विद्युत घर भी निर्माणाधीन है, आखिर वो पूंजीपति है, इसलिए पूंजीपतियों की ही वकालात करेगा, यदि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की मात्र रु. 13000 करोड़ की पूंजी आयेगी तो उनकी कोशिश होगी कि वो निवेशित पूंजी से कई गुना ज्यादा लाभ बटोर कर हर वर्ष विदेश भेजें, दूसरी ओर जितनी भी विदेशी पूंजी आयेगी उससे कई गुना ज्यादा मुद्रा स्फीति बढ़ेगी, वर्तमान में पारले, आईटीसी, हिन्दुस्तान लीवर, रिलायंस जैसी बड़ी कं. 2रु. का आलू चिप्स का पैकेट रु. 15 से 25 में बेच रही है। लूट तो आम आदमी ही रहा है, फिर आर.एस.एस. की स्वदेशी की अवधारणा कहां गई, सारी प्रशासनिक व्यवस्थायें इन बहुराष्ट्रीय कं. पक्ष में केंद्रीयकृत होती जा रही है। आर.एस.एस. उसके राजनैतिक दल भाजपा, किसान मोर्चा के शीर्ष में बैठे पदाधिकारीगण अच्छी तरह से जानते हैं कि राष्ट्र की सारी अर्थव्यवस्था को गुलाम बनाने की साजिश चारों तरफ चल रही है। सभी बहुराष्ट्रीय कं. का उद्देश्य धन कमाना है, कल्याण के लिये भारत में विनियोजन करने नहीं आये हैं। इन हरामखोर जालसाज गिद्धों ने आने से पहले ही अपने पक्ष में कानून बनवा लिये, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि.06 जो पूर्णतः छोटे किसानों से लेकर छोटे फुटकर व्यापारियों, दुकानदारों तक को पूर्णतः समाप्त करने के लिये इस तरीके से बनाये गये हैं ताकि ये अपनी खेती, फुटकर व्यवसाय कर ही न सकें और करें तो इतने कानूनों में उलझाकर, उस पर उल्लंघन का आरोप लगाकर भारी अर्थदंड और कारावास तक पहुंचा दें। शायद आर.एस.एस. और उसके किसान संघ ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधि.06 नहीं पढ़ा। बेशक आर.एस.एस. की भाजपा के सांसदों ने इस कानून को पास करवाने में बंटे अरबों रु. की सौदेबाजी में न केवल हिस्सेदारी ली और आंख मींचकर उस कानून को पास करवाने में अंध सहमति दी, जिसमें म.प्र. का वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज भी अधिनियम की समिति का भी सदस्य था, तब तो कानून बिना पढ़े हस्ताक्षरित कर दिया जब अन्ना के आंदोलन की आड़ में 5 अगस्त 11 से कानून लागू किया और जब उसका असर पड़ने लगा और 9,10,11 अप्रैल 12 को पूरे प्रदेश में आंदोलन किया गया तो ये फिर ये जालसाज मुख्यमंत्री शिवराज दलीलें देने लगा, साथ ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने के लिए हजारों हेक्टेयर जमीन, कम कीमत पर बिजली, पानी, सड़कें, रेलवे लाइन देने की भी पेशकश कर रहा है। उन्हीं किसानों को हजारों हेक्टेयर भूमिहीन कर, जिनके हितों की निगरानी के लिये किसान संघ ढोंग कर रहा है। किसानों से न केवल उनकी कृषि भूमि छीनी जा रही हैं, वरन उनके लिये खरीदी गई बिजली भरे सिंचाई के मौसम में किसानों को न देकर और दी भी जाती हैं, तो न केवल महंगी वरन 24 घंटे में से मात्र 4 से 8 घंटे मात्र वह भी रात्रि में जब शहरों में, फैक्ट्रियों में मांग कमजोर हो जाती है, दूसरी ओर डीजल पर सबसे ज्यादा टैक्स म.प्र. में लगाया जा रहा हैं, आखिर किसान संघ ने सस्ती बिजली, उद्योगों के लिये छीनी जा रही कृषि भूमि के लिये खाद, बीज, टैक्स कम करके सस्ते डीजल की क्या कृषकों के हित में मांगें उठाईं, जिन्होंने मांगे उठाईं उन्हें जेल में डाल दिया गया और किसान संघ ने उस शर्मा को भी बाहर का रास्ता अपने राजनैतिक आकाओं के कहने पर दिखा दिया आखिर जिस व्यक्ति ने कृषक हित की बात की उसे यदि बाहर का रास्ता दिखा दिया तो बचे हुए पदाधिकारी क्या राजनैतिक लाभ के लिये बहुराष्ट्रीय कं. के इशारे पर चलकर उनसे मोटी दलाली डकार कर न केवल किसानों का शोषण कर रहे हैं वरन अन्य राजनैतिक दलों की तरह दोमुंही चालें चलकर केवल स्वार्थ सिद्धी में लगे हैं।

उन्हें मोटा चंदा मिले, वोट मिलें, म.प्र. सड़क परिवहन निगम, म.प्र. विद्युत मंडल को समाप्त कर सब अपने स्वार्थसिद्धी में लगे हुए हैं। जहां एक तरफ म.प्र.स.पि.निगम को समाप्त कर अकेले भाजपा के ईश्वरदास रोहणी की हजार से ज्यादा बसें चल रही हैं, वहीं सभी कांग्रेसियों, भाजपाई, पुलिस और परिवहन निगम के अधिकारियों-कर्मचारियों की बसें चलाकर जनता के यात्रियों का तन, मन, धन से शोषण किया जा रहा है। वहीं म.प्र. विद्युत मंडल को बर्बाद कर कंपनियां बना दी गई, ये कंपनियां वर्ष में 2-3 बार कीमतें बढ़ाती हैं। इसके बाद भी न तो बिजली 24 घंटे दे पा रही हैं। दूसरी तरफ जनता को अनाप-शनाप बिल देकर उन्हें आत्महत्या तक पर मजबूर कर रही हैं। गांवों में तो मात्र 4-6 घंटे बिजली दी जा रही हैं। फिर भी उन ग्रामीणों और किसानों को हजारों रु. के अनाप-शनाप बिल भेजे जा रहे हैं। जमा न करने पर जेल भेजा जा रहा हैं, क्या किया किसान संघ ने जो भाजपा का कृषि क्षेत्र का मुखौटा हैं।

इसी संदर्भ में 5-6 अक्टू. 12 को फूल मंडी में इन किसान संघ के पदाधिकारियों ने भाजपा के भूमाफिया के इशारे पर उस 50 वर्षों से ज्यादा समय से लग रही मंडी के किसानों 30 टन से ज्यादा फूल फेंक दिये उस किसान से पूछो जिसने 3-4 महीने के अथक परिश्रम से फूल पैदा किये थे, इस किसान संघ के हरामखोरों ने उन किसानों की कितनी बर्बादी की, बेशक कहा ये गया कि किसानों ने फूल फेंके इस पंढ़रीनाथ की फूल मंडी को बंद करके चोइथराम मंडी ले जाने के लिये, जिसे शासन-प्रशासन ने भी यही प्रचारित किया कि किसानों ने फूल फेंके, किसानों को अगर फूल फेंकना ही थे तो वो यहां लेकर ही क्यों आता? दूसरा कौन मूर्ख होगा जो अपने लाखों रु. का माल बर्बाद करेगा, जिसमें उसने महीनों अपना खून-पसीना बहाया हो, कुल मिलाकर कहानी का सारांश यह था कि ये फूल व्यापारियों से यहां तो थाना बाजू में होने के कारण चंदा वसूल नहीं पाते, फिर भाजपा में बैठे भूमाफियाओं की नजर उस फूलमंडी की जमीन पर वर्षों से लगी हैं, जिनके चेले-पट्टे अभी इंदौर नगर निगम में पार्षद हैं। जिसे मंडी सचिव नागर और इंदौर की कृषि उपज मंडियों के सचिव व उप जिलाधीश मंडलोई की भी मूक सहमति थी, उन्होंने पंढरीनाथ पर जिन किसानों की फसलें बर्बाद की गई और व्यापारियों के साथ इन किसान संघ के लोगों ने लड़ाई-झगड़े और मारपीट की थी की पंढरीनाथ थाने पर रिपोर्ट नहीं लिखवाने दी, अब चोइथराम मंडी में लाखों रु. की नीलामी में दुकानें खरीदें व्यापारी जिनसे सारे हरामखोरों को मोटी कमाई मिले। नेताओं को भी, सरकारी अधिकारियों को भी बाद में अवैध वसूली नेताओं की चंदे की हो, सरकारी अधिकारियों की तो होगी ही। साथ ही बहुराष्ट्रीय कं. की जो गिद्ध निगाहें लगी हैं कि किस किसान की जमीन पर कौन सी अच्छी फसल पैदा हो रही हैं, किसके पास कितनी जमीन है से लेकर सारा माल कब्जे में लेकर अपने भावों पर बेचो। क्या ऐसे ही हैं किसान संघ के पदाधिकारी और सरकारी मंडी के अधिकारी जो किसानों की बर्बादी कर केवल अपने स्वार्थ सिद्धी में लगे हैं। जिन्हें किसानों के हितों से बिल्कुल भी सरोकार नहीं उन्हें तो केवल अपने नोट, वोट और किसानों की भीड़ भर चाहिये, ताकि अपना रुतबा अपनी अहमियत दिखाई जा सके।

भारत सरकार जिस फुटकर व्यवसाय में विदेशी निवेश के लिये पूरे पेज के विज्ञापन छान कर अभी कह रही हैं, किसानों को उचित मूल्य तत्काल में जब तक बाजार हैं, मंडी हैं। प्रतिस्पर्धात्मक अच्छे मूल्य मिलेंगे, पर जब पूर्णरूप से ये बहुराष्ट्रीय कं. एकाधिकारी व्यवसाय करेंगी तो न तो मंडियां रहेंगी, न किसान रहेगा और न व्यापारी रहेगा, सारे उपजाऊ खेतों पर बहुराष्ट्रीय कं. का कब्जा होगा, यांत्रिकीयकरण से खेती होगी, अपना मूल्य न्यूनतम दरों पर पैदाकर अपनी कीमतों पर बेचा जाएगा। दूसरी ओर जो कृषक अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे, बेचेंगे या कंपनियों को नहीं सौपेंगें वे फसल पैदा भर करेंगे पर उसका परिवहन कर मंडी या खेत से कहीं भी बाहर नहीं ले जा सकेंगे। यह खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि. 06 में लिखा हुआ है, कंपनियां सीधे खेतों पर पहुंचकर अपने भाव से माल खरीदेंगी किसानों से, अर्थात भविष्य के इस घोर शोषण की बहुराष्ट्रीय कं. की ये कहानी जो 2-3 वर्ष में ही साकार होने वाली है, किसानों संघ ने क्या किया अभी तक सन् 2006 से 2012 तक, तो चुप्पी मारे इसीलिये बैठा है, कि उसने भी इन बहुराष्ट्रीय कं. से मोटा माल अंटी कर लिया है, जबकि किसानों के हाथ से जमीन जाते ही या माल मंडी न ले जा सकने की अवस्था में भी घोर शोषण ही किया जायेगा जिसमें फसल की लागत भी नहीं निकलेगी जमीन के बाजार मूल्य की पूंजी का ब्याज तो निकलना दूर की कौड़ी है।

किसान संघ अप्रत्यक्ष रूप से इन बहुराष्ट्रीय कं. की, इन राजनैतिक दलों के नेताओं के निजी स्वार्थों के चलते कठपुतली बन नाच रहा हैं, अपनी बिजली, पानी, सड़कों, खाद, बीज, सरकार द्वारा औद्योगीकरण के लिये जमीन छीनकर औद्योगिक नगरी बनाने, कृषि भूमि नष्ट करने के षड्यंत्रों के बारे में अपने हितों के लिये लड़ाई क्यों नहीं लड़ता। घोर नौटंकीबाज एक तरफ तो आदिवासियों की लाखों एकड़ जमीनें न केवल सरदार सरोवर, इंदिरा सागर, औंकारेश्वर, मंडलेश्वर बांधों में डुबोने के साथ ही कालोनाइजरों, बिल्डरों, उद्योगपतियों के लिये छीन रहा हैं, दूसरी तरफ 50000 आदिवासियों की जनचेतना रैली में शामिल होकर उनके साथ 10 कि.मी. तक सायकल चलाने की नौटंकी की, जब किसान संघ ने कोई भी कटाक्ष तक नहीं किया, जबकि आदिवासियों के साथ धूर्त शिवराज ने खुले में छल किया, नाम शिवराज काम राक्षसों की तरह लूट-खसोट, झूठ बोलना।

म.प्र. स्वा. विभाग जालसाज डकैतों के अड्डे हैं

केन्द्र, राज्य व विदेशी धन के साथ मरीजों से भी वसूली

एनआरएचएम आरसीएच के साथ अनेकों विभागों में कागजी जमा खर्च कर 80% जाता है। रु. 25 करोड़ से 50 करोड़ तक हर जिला मुख्यालयों पर मरीजों से नोचखसौट में अब निजी अस्पताल भी शामिल

म.प्र. स्वास्थ्य विभाग में बैठा हर डाक्टर और कर्मचारी चाहे अदने से कर्मचारी तक भारी जालसाज भ्रष्टों और मक्कारों से भरा हुआ है, ये हालात केवल म.प्र. के ही नहीं पूरे राष्ट्र के अधिकांश पूरे विश्व में लोकतांत्रिक राष्ट्रों के भी हैं। निःसंदेह यह सच है कि स्वा. के नाम पर न केवल सरकारी वरन् निजी चिकित्सालयों में ये डॉक्टर्स यथार्थ में एप्रिन के वो सफेद गिद्ध हैं जो जीवित बीमारों और उनके परिजनों को तो लूटते ही हैं। मरने के बाद भी जालसाजी पूर्ण तरीके से उसे कृत्रिम सांस नली, एयर पम्प लगाकर और कप्पूर्स लगाकर भी लाखों रुपए मरीजों उनके परिजनों से लुप्ते हैं और गिद्धों की भांति उनकी आंखें, किडनी, लीवर तक मृत देह से नोचकर बेंच खाते हैं। फिर भी इन गिद्धों की हवस शांत नहीं होती। निजी चिकित्सालयों में तो धन के लिए जबकि हर सेवा का, दवाइयों, शल्यक्रिया भी लाखों रुपए वसूलने और मनचाही कीमतें, जिसमें आईसीयू, दैनिक किराए, कर्मचारियों, डॉक्टरों आदि की जांचों की वसूली के लिए शवों तक को रोककर रखा जाता है, शवों को भी तभी दिया जाता है, जब उनकी पूरी कीमत वसूल ली जाती है। इसमें परिजनों के मकान, दुकान, जमीन जायदाद सब बिक जाए लाखों रुपए के कर्जे हो जाए पर ये नीच गिद्ध अपनी नोंच खसोट से बाज नहीं आते। यही कारण है कि पूरे देश में चिकित्सा व्यवसाय खूब फल-फूल रहा है।

सरकारी चिकित्सालयों में भी जितने डॉक्टर्स, नर्सेज व दूसरा स्टॉफ बैठा है, एक तरफ तो शासन से मिलने वाली औषधि का करोड़ों रुपया हजम कर जाता है, तो दूसरी तरफ मरीजों से भी हर बात के पैसे वसूले जाते हैं। हाल ही में शासकीय स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सालयों, चिकित्सा महाविद्यालयों तक में करोड़ों रुपए के कमीशन डकारने का साल दो साल से नया खेल शुरू हो चुका है। इस खेल में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों से लेकर चिकित्सालयों में पदस्थ डॉक्टर्स जो ऐसे कार्यों की स्वीकृति देते हैं। करोड़ों रुपए साल का कमीशन डकार जाते हैं। इन जालसाजियों में जो सूचना के अधिकार में प्राप्त हुई सबसे ज्यादा फर्जी प्रकरण बना कर, जांचों के नाम पर निजी अस्पतालों की तरफ मरीजों को भेजकर शासकीय चिकित्सालयों के मुफ्त इलाज की सत्यता में कितनी सत्यता है वह प्रगट होती है। दूसरी तरफ इन निजी चिकित्सालयों को फायदा पहुंचा कर उनका पेट भरने के साथ स्वयं का भी कमीशन हजम करने के रास्ते ऊपर संचानालय से ही खोल दिए गए हैं। जान बूझकर ये सरकारी चिकित्सक उठी सीधी जांचों को मरीजों को उनके एक भज्जा, थूक, मूत्र, विष्य आदि के लिए निजी चिकित्सालयों, पैथालॉजी में भेजा जाकर उसके पैसे मरीजों से वसूली जाते हैं। दूसरी तरफ उन्हीं जांचों के बिल सरकारी कार्यालयों से भी भुगतान करवा दिए जाते हैं। यह हाल म. गां. चिकित्सा महाविद्यालय से लेकर, जिला अस्पतालों जिसमें धार, इंदौर, उज्जैन, देवास से लेकर पूरे प्रदेश में और देश में खेला जाकर एक तरफ अरबों रुपए से जालसाज गिद्धों की फौज सरकारी धन से लूटकर डकार रही है तो दूसरी तरफ मरीजों को भी अरबों रुपए नोचकर कमीशन डकार रही है, इस प्रकार इंदौर का विशेष हॉस्पिटल गीता भवन चौराहे व अन्य अस्पतालों से लेकर जांचों को जानबूझकर अहमदाबाद और हैदराबाद तक भेजा जाता है।

(शेष पेज 5 पर)

साप्ताहिक समय माया

म.प्र. शासन का सौतेला विभाग खाद्य एवं औषधि

शासन बेपरवाह-जनता कल की मरती आज मरे

दुधारु पशु ही नहीं 90% दूध नकली, खाद्य-औषधि निरीक्षकों को वसूली से फुर्सत नहीं, फिर स्टाफ और सुविधाओं का घोर अभाव

म.प्र. शासन का महत्वपूर्ण विभाग, जनता के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से खाद्य एवं औषधि है, जो जनता के खाद्य एवं औषधि की शुद्धता एवं प्रमाणिकता के साथ ही उसके स्वास्थ्यवर्धक होने की जिम्मेदारी निभाता है, पर म.प्र. शासन में बैठे न केवल धूर्त और भ्रष्ट मुख्यमंत्री और मंत्रियों से लेकर घोर मक्कार, भ्रष्ट, गिद्धों की इंडियन एव्युसिंग सर्विस अधिकारियों की फौज की नजर भी मात्र चाहे वह फिर मुख्य सचिव परशुराम हो या प्रधान सचिव, सचिवों से लेकर, आयुक्तों, संचालकों, जिलाधीशों, उपजिलाधीशों तक सबको न केवल धन चारहिये, इसके लिये नियम कानूनों को तोड़ने-मरोड़ने अपनी तरह से व्याख्या कर अपने लाभ के लिये ही सारे कृत्य करते हैं। उनकी निगाह में जनता चीटिंयों और जानवरों से ज्यादा कुछ भी नहीं होती हैं। जहां तक प्रशासनिक अधिकारियों का सवाल हैं, तो कानून इनकी रखैल और छोटे अधिकारी गधे-घोड़े, खच्चरों से व कर्मचारी भेड़-बकरियों से ज्यादा कोई औकात नहीं रखते हैं। इसीलिये ये सब कानूनों से ऊपर इस देश के असली खुदा है, जो इस राष्ट्र को हांकते हुए अपनी अय्याशियों, मौजमस्ती करते हुए जिंदगी गुजारते हैं। उन्हें जनता के स्वास्थ्य से क्या मतलब है। स्वाभाविक है कि उसके स्वास्थ्य विभाग उससे जुड़े खाद्य एवं औषधि विभाग जहां प्रदेश की 7 करोड़ आबादी के स्वास्थ्यवर्धक खाद्य और स्वास्थ्य बनाये रखने के लिये जनात के बीमार पड़ने पर दी जाने वाली औषधियों के उत्पादन, गुणवत्ता, उसके विक्रय की नियति तक देखने वाले इस विभाग में पूरे प्रदेश में मात्र 25 औषधि निरीक्षक हैं, जबकि यदि 5 लाख की आबादी पर एक औषधि निरीक्षक की आवश्यकता मानें तो भी कम से कम 140 औषधि निरीक्षक न्यूनतम होने ही चाहिये प्रदेश के 50 जिलों में, यही हाल खाद्य निरीक्षकों का भी है, यदि 2 लाख की आबादी पर एक निरीक्षक आवश्यक मानें तो भी 350 खाद्य निरीक्षकों की आवश्यकता पर मात्र 175 खाद्य निरीक्षक हैं, जिनमें अधिकांश अनुभवहीन और वसूलीबाज हैं। देवास में ही लें, यहां बैठी खा.नि. सुषमा पथरोल और खा.नि. निर्मला लोंगरिया थोड़ी अनुभवी हैं, तो उन्हें जनता के स्वास्थ्य से कम, वसूली से ज्यादा मतलब होता है, यही कारण है कि अमूल जैसी विख्यात गुजरात की दुग्ध सहकारी संस्था की अमूल दुग्ध पैकिंग का कार्य प्रीमियर फूड एंड नट्रीशियंट जैसी कं. के द्वारा स्तरहीन बिना 6 से 8 % वसा के दूध में 2% भी फेट नहीं होता क्योंकि सूत्रों के अनुसार लाखों रुपए माह की वसूली खाद्य निरीक्षक सुषमा पथरोल को देता है।

देवास की कुख्यात अग्रवाल की सूरज इंडस्ट्रीज जो नकली हल्दीकांड में कई बार पकड़ा जा चुका हैं, टनों से पीली मिट्टी जब्त होने के बाद अभी भी खा.नि. सुषमा पथरोल को वसूली देता है। नाम बदलकर अभी भी हल्दी की पैकिंग कर रहा हैं, ऐसे सैकड़ों हैं। जो अभी खाद्य वस्तुओं में मिलावट कर जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। बस खाद्य निरीक्षकों को महीना बांटकर उनका व्यवसाय धड़ल्ले से चला रहे हैं। जबकि खा.नि. सुषमा पथरोल को 3 वर्ष में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए था। 6 वर्ष से ज्यादा समय से लूटो और 25% लुटाओ के दम पर जमी हैं। दूसरे खाद्य निरीक्षकों से छोटे-मोटे काम करवा के उन्हें बैठाये रखा जाता है यही हाल उज्जैन का भी है यहां भी खा.नि. वर्षा व्यास जिस खा. एवं ना. आपूर्ति मंत्री पारस जैन का वरद हस्त है। केवल वसूली में ही व्यस्त रहती है।

पारले की मैंगो बाइट टाफियों का मुंबई-ठाणे में नमूना लिया गया, उसमें लेक्टिक एसिड पाया गया जो विषैला था, खाद्य एवं औषधि प्रशासन महाराष्ट्र ने आदेश दिया कि पूरा माल बाजार से वापिस मंगवायें, फिर सोचने वाली बात थी नाम मैंगो बाइट, मैंगों तो है नहीं, इसलिए लेक्टिक एसिड मिलाकर दिया। म.प्र. के जालसाज निरीक्षकों ने क्यों नहीं पकड़ा, क्योंकि महीना बंट रहा है, इसलिये क्या जरूरत हैं, एक भी ब्रांड पकड़ेंगे तो महीना ही बंद हो जायेगा, इसलिए मिस ब्रांड करते हैं मिलावट नहीं पकड़ते।

नये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि.06 के अंतर्गत नगर निगमों, पालिकाओं के अंतर्गत में कार्य कर रहे सारे खाद्य निरीक्षक जिसे अब खाद्य सुरक्षा अधिकारी कहा जाता है, सबकी सेवायें खाद्य एवं औषधि विभाग को सौंप दिये जाने के बाद भी सवा साल गुजरने के बाद भी वे सभी अपनी लूट और वसूली करते हुए सारे जालसाज अभी भी निगमों और पालिकाओं के अंतर्गत सेवायें देते हुए पार्षदों और स्वास्थ्य अधिकारी निगम और पालिकाओं के कमाई और वसूली के हथियार बनकर मासिक वसूली तो कर ही रहे हैं वरन् महापौरों, स्वास्थ्य अधिकारियों, पार्षदों जो स्वास्थ्य समिति का अध्यक्ष हैं, ने उन्हें अवैध रूप से क्षेत्र का आवंटन कर दिया है, ताकि इन हरामखोर, जालसाज निगम और पालिकाओं के खाद्य निरीक्षकों की महीना वसूली निर्बाध चले और औषधि एवं खाद्य सुरक्षा के निरीक्षक सह खाद्य सुरक्षा अधिकारी उनके इन अवैध रूप से चलाये जा रहे कृत्यों में दखलंदाजी भी न कर सकें, ये हाल इंदौर, उज्जैन, भोपाल, देवास, धार, शाजापुर, ग्वालियर, सागर, जबलपुर सभी जगह चल रहा हैं, जबकि इनकी सेवायें यथार्थ में खा.सु.व.मा. अधि.06 में शासन के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन कर दी गई है। इसके विपरीत प्रदेश के निगमों, पालिकाओं के महापौर, निगमायुक्तों, स्वास्थ्य समिति अध्यक्षों ने न तो इनकी सेवायें मु.स्वा. अधि. को सौंपी और न ही इनके अंतर्गत कार्यरत खाद्य निरीक्षक जाना चाहते क्योंकि सबकी अवैध महीना वसूली, डरा-धमकाकर चंदा वसूली बंद हो जायेगी, यही कारण है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के महीना वसूली के साथ विभागीय कार्य भी ढंग से संपन्न नहीं कर पाते, चाय चाट-पकौड़ी, फुटपाथ पर फलों के रस बेचने वालों से लेकर सभी किराना व्यवसायियों, दुग्ध विक्रेताओं, जो सायकलों मोटर सायकलों से दूध बेचते हैं, से लेकर हर खाद्य व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति को नये अधि. के अंतर्गत पंजीयन व लायसेंस लेना अनिवार्य हैं, पर न केवल इंदौर, देवास, उज्जैन, धार, रतलाम, शाजापुर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर आदि पूरे प्रदेश में इस लायसेंस को लेकर कोई विशेष हलचल नहीं है। लायसेंस बनाने के चक्कर में खाद्य विभाग को नमूने लेने का कार्य काफी धीमा हो चुका हैं, जबकि शहरों में 70% दूध नकली आपूर्ति किया जा रहा है, क्योंकि पूरे प्रदेश की 7 करोड़ की आबादी में 70 लाख दुधारु पशु भी नहीं है, यहां तक की गांवों की आबादी 1000 है तो 100 दुधारु गाय भैंस भी नहीं है। फिर शहरीय आबादी के तो 1% भी नहीं हैं। तो आखिर साढ़े तीन करोड़ ली. दूध म.प्र. में कहां से प्रतिदिन आपूर्ति की जा रही है। गरीबों को तो दूध के दर्शन ही दुर्लभ है। गरीबी रेखा से ऊपर वालों को जरूर चाय, काफी, दूध पीने की आदत हैं, मध्यम व उच्च मध्यम, उच्च वर्ग में ही दूध की खपत ज्यादा होती हैं, जब दूध बच्चों के लिये व वयस्कों की चाय-काफी, आइसक्रीम, लस्सी आदि में ही पूरा नहीं पड़ रहा तो मक्खन, पनीर, घी, मावा, मिठाई के लिये दूध किस आसमान से बरस रहा हैं, आखिर क्यों सांची, अमूल के साथ अनिल, सौरभ जैसे पेक्ड दूध के नमूनों के साथ ही हर शहर के प्रवेश मार्गों पर सुबह 5 से 8 बजे तक और शाम 5.30 बजे से 7 बजे तक हर सायकल मोटर सायकल, आटो लोडिंग, ट्रकों से जो दूध आ रहा है उसके नमूने लिये जाते। बेशक निगम के खाद्य निरीक्षकों को वर्षों से सबसे महीना बंधा हुआ है, जो 1 से 10 तारीख तक हर महीने इन दूधियों से महीना वसूली कर लाखों रु. कमाते हैं। दूसरी तरफ गांवों में जो दूध आपूर्ति करते हैं वर्षभर रबी-खरीफ की फसलों के अतिरिक्त बोरियों से हर दिन ट्रक वाले खाद्य व डिटरजेंट ले जाकर क्या करते हैं या टी.वी. पर नकली दूध की कहानी हर गांव में वर्षो से रोज दोहराई जा रही हैं। पूरे शहरीयों को 70% दूध नकली पिलाया जा रहा है, इसके विपरीत निगम-पालिकाओं के खाद्य निरीक्षकों से लेकर खाद्य एवं सुरक्षा के निरीक्षक सह सुरक्षा अधिकारियों तक सब महीना वसूली कर तान के सो रहे हैं। जिलाधीशों,मु.चि.एवं स्वा. अधिकारियों तक महीना पहुंच रहा हैं, वहां से खाद्य नियंत्रक, स्वा. मंत्री तक उनका हिस्सा पहुंच रहा हैं इसलिये किसी भी हरामखोर जालसाज को फुर्सत ही नहीं हैं, जबकि ब्रांडेड कं. जिसमें ब्रिटानिया, पारले, आई.टी.सी., जैसी राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कं. बाजार में अकेले म.प्र. में ही प्रतिदिन विभिन्न ब्रांडों के क्रीम बिस्कुट बेचकर अरबों रु. इकट्ठा कर रही हैं। वह पूरी क्रीम, मक्खन सब नकली हैं, इस विभाग से जब जानकारी ली गई तो जो नमूने लिये गये, मोटी रकम वसूल कर केवल मिस ब्रांड, समय बाधित के प्रकरण बनवाकर छोटे-मोटे दंड भरवाकर इन जहरीले नागों को, जिसमें पारले, ब्रिटानिया आदि अनेकों कं. थीं, जिनके बिस्कुट हर सुबह प्रदेश के और देश के करोड़ों बच्चें खा रहे हैं, जिससे बच्चों को बचपन में ही बड़ों की बीमारियां हो रही हैं। छोड़ दिया जा रहा है, जबकि उसमें रंग, खाद्य संरक्षक के साथ एंटी फंगस, एंटी वैक्टीरिया रसायनों के साथ मिठास के लिये शक्कर के अतिरिक्त रसायन मिलाये जा रहे हैं। ताकि इन ब्रांडेड कं. को गोली, बिस्कुट, चाकलेट व अन्य खाद्य सामग्री खराब न हो जबकि यह सारा माल फैक्ट्री से निकलकर छोटे-बड़े शहरों, गांवों तक ये पेकेज्ड फूड महीनों लग जाते हैं। ये पेकेज्ड फूड जिसके 24 घंटों हर चैनल पर विज्ञापन चलते रहते हैं। इन चॉकलेट, बिस्कुटों के सेवन से बच्चों की पाचन शक्ति तो कमजोर हो ही रही है, साथ ही मोटापा, किडनी, फेफड़ों, पेट में कब्जियत, वायु, अपवंचन, हर्निया, अपेन्डिक्स से लेकर हृदयघात तक की बीमारियां होने के साथ नपुंसकता, आलस, हाथ-पैरों में कंपन तक की शिकायतें बच्चों में देखी जा रही है। समयपूर्व बुढ़ापे के लक्षण वालों की सफेदी से लेकर अकाल मौत के शिकार हो रहे हैं बच्चों से लेकर युवा पीढ़ी तक, आखिर पूरा खाद्य और औषधि विभाग की प्रयोगशालाओं के पास इतनी साधन संपन्नता क्यों नहीं हैं कि इन बहुराष्ट्रीय कं. रूपी नागों के खाद्य पदार्थों में मिलाये व फैलाये जा रहे सैकड़ों किस्म के जहर रूपी रसायनों को पकड़ के इनकी कं. बंद करवाई जा सके, पर हर शासकीय विभाग के कर्मचारी अधिकारियों से लेकर नियंत्रक, सचिव, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य तक सब गुलाम हैं हरामखोर पैसे के, मंत्री और मुख्यमंत्री तो बेचारे कटोरा लेकर ही पैदा हुये हैं, इन्हें तो पांच साल में जितना बटोर सके बटोर लें, चुनाव हारने पर सड़क का कुत्ता भी नहीं भौंकता, तो जनता के स्वास्थ्य की फिक्र करें या अपने बैंक बैलेंस की, फिर ये खाद्य विभाग ही गाहे-बगाहे कोई कार्यवाही करता भी है, तो सब सत्ताधीश मंत्रियों, संत्रियों के फोन आना शुरु हो जाते हैं, कि तो हमारा कार्यकर्ता है, जहर भी खिलाये तो नमूना मत लो जो लेन-देन हो कर लो, छोड़ दो हर बड़ा खाद्य व्यवसायी किसी नेता, पार्षद, मंत्री से जुड़ा होता है। ताकि उसकी मिलावटी गतिविधियों को बचाया जा सकें, आने वाली दीपावली पर सारे देश में, प्रदेश में, शहर से लेकर गांवों तक 99% दूध की मिठाइयां नकली दूध की बनेंगी पर किसी का कुछ नहीं होगा। टनों से नकली मावा पकड़ा जाता हैं, किलों से फेंका जाकर टीवी चैनलों पर फोटो दिखाकर वाहवाही लूटी जाती हैं, बचे हुए मावे का लेन-देन होकर मिठाई बनाकर करोड़ों रु. अंदर कर लिये जाते हैं। हजारों का चंदा पक्ष-विपक्ष के नेता जीम जाते हैं। तो शासन कैसे इन्हें स्टॉफ दें, अच्छी प्रयोगशाला बनवाये, इस खाद्य एवं औषधि विभाग को जीप-कारें दें, स्टेशनरी दें, अच्छा फर्नीचर व अन्य सुविधायें दें। सौतेला व्यवहार तो करना जरूरी है, नहीं तो सारे मिलावटिये पकड़े गये तो पार्टी ही खत्म हो जायेगी।

इस खाद्य एवं औषधि विभाग से सूचना के अधिकार में जानकारी मांगी गई जिसमें खाद्य एवं औषधि निरीक्षकों की 6 माह की दैनंदिनी या डेली डायरी मांगी गई थीं, खाद्य निरीक्षकों ने तो झूठी सच्ची डेली डायरी की प्रतियां उपलब्ध करवाई, जो इनकी कानूनी आवश्यकता थी, परन्तु यहां बैठे धूर्त व हरामखोर औषधि निरीक्षकों ने तो डेली डायरी न तो बनाई और न ही बनायेंगे यह कर साफ मना कर दिया जब अपील में गये तो मालूम पड़ा कि मु.चि. एवं स्वा. अधि. जिसे जानकारी देनी चाहिये थी, जो कि हर जिले का इस विभाग का मुखिया भी हैं, वही इनका अपीलेट अधिकारी भी हैं। डॉ. डागरिया जो कि वर्तमान में इंदौर के सीएमओ हैं ने भी साफ कह दिया कि जब बनाई ही नहीं हैं, तो किसकी फोटो कापी दी जाये और जानकारी बना कर दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं हैं। पूरे म.प्र.में मात्र 25 औषधि निरीक्षक हैं जिसमें से 4 अकेले इंदौर में हैं। जिसमें औ.नि. वृन्दानी जो सबसे ज्यादा मक्कार,

जालसाज तो है ही महीने की रु. 20-25 लाख की वसूली भी करता हैं, फिर ओ.नि. अजय ठाकुर, अशोक गोयल नये होने के कारण अभी वसूली के पैंतरे सीख रहे हैं। फिर भी रु. 50 हजार महीने की वसूली दवा दुकानों से, उत्पादकों से झटक ही लेते हैं। चौथे हैं वरिष्ठ औ.नि. शोभित कोष्ट, सप्ताह में तीन दिन इंदौर में, 3 दिन भोपाल में बैठते हैं। जो उत्पादन लाइसेंसिंग, प्रमाणीकरण करते हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनकी वसूली का भी, यदि सभी औषधि विक्रेता उत्पादक, पैकर्स के यदि ये नमूने लें भी लें और लेन-देन के अभाव में न्यायालय में चालान लगा भी दें, तो आसानी से डेली डायरी के अभाव में ये विभागीय मुकदमा हार सकते हैं। क्योंकि डेली डायरी बतौर साक्ष्य, आरोपी न्यायालय में बुलवा सकता है। औ.नि. वृंदावनी जो वर्षों से कुंडली मारे इंदौर में बैठा हैं, तो हर वर्ष मोटा चढ़ावा जो कि लाखों में होता है चढ़ाता हैं, तो बेचारा कमायेगा नहीं तो चढ़ायेगा कहां से, फिर हरामखोरी, जालसाजी और वसूली तो मु.स. से लेकर शासकीय विभाग के चपरासी तक के खून में समाई हैं, तो बेचारे ये तो मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, आयुक्त से बहुत नीचे हैं। फिर प्रदेश में तो 50,000 से ज्यादा औषधि विक्रेता हैं वसूली तो समय पर हो नहीं पाती इन पर छापे मारकर नाइट्रावेट, नशीली अन्य दवायें बिना पर्ची के बेची जा रही हैं, समय बाधित या प्रतिबंधित बेची जा रही हैं। विक्रेता, उत्पादक, नियम कानूनों का उल्लंघन कर रहा है कैसे देखें, फिर यही देखने बैठ गये तो फिर वसूली कौन देगा और किस बात की फिर महंगाई कितनी बढ़ रयही हैं, फिर कहीं महीना बांटना है तो कहीं तिमाही, कहीं छः माही और कहीं वर्ष में एक बार, फिर पत्रकारों को दैनिक निकालते हैं। उन पर भी खर्च करना हैं, ताकि इन खाद्य व औषधि निरीक्षकों के झूठे सच्चे कहानी किस्से छापते रहें, ताकि खाद्य व औषधि निर्माता विक्रेता चौंकते चमकते रहें और धंधा वसूली का चलता रहे, जनता खाद्य से मरे तो औषधि से ठीक हो, यदि औषधियों से भी मरे तो भाई वह तो पैदा ही मरने के लिये हुई है। क्या इन खाद्य और औषधि वालों की ये जिम्मेदारी है कि जनता न मरे, कोई ठेका तो लिया नहीं है इन बेचारों ने।

लो.नि.वि. में सभी भ्रष्टाचार के कुख्यात

सूचना के अधि. में जानकारी मांगने पर करते हैं जालसाजियां

25 से 60 प्रतिशत पैसा हजम, सारे सेतु दुगुने समय से ज्यादा में

म.प्र. लोक निर्माण विभाग भ्रष्ट, ढीला और निकंमा मंत्री नागोद और उसका प्र.स. केके सिंग जो वर्षों से कुंडली मारे केवल पाइप लाइन से पूरे प्रदेश से पहुंचने वाली मोटी रकम जो अरबों रुपए में होती है, हजम करने ही बैठे हैं। एक तरफ मुख्य मंत्री घोषणा करते हैं। अच्छी सड़कें हैं, पूरे प्रदेश में और निवेशकों की भीड़ बुलाकर रुपए 500 से 1000 करोड़ की बर्बादी करता है, जबकि दूसरी ओर पूरे प्रदेश में बैठे हर जिले का कार्य पालन यंत्रियों को महाभ्रष्टों को चुन-चुनकर बैठाया गया है, जिनकी अरबों रुपए की सड़कों का निर्माण और सुधार कार्य कागजों पर ही पूरा होकर 25 से 60-70 प्रतिशत पैसा हजम किया जा रहा है। भवन और पुलों में जहां इतना धन हजम करना संभव नहीं होता, वहां जानबूझकर पूरा सेतु जोन जिसमें बैठे शूकरों की फौज उपयंत्री, सहायक यंत्री कार्यपालन अधीक्षक यंत्री से मुख्य यंत्री तक जानबूझकर कोई भी पुल, रेलवे ओवर ब्रिज को समय से दोगुने-चौगुने समय तक अधूरा रखकर कीमत बढ़ाने में धन 25 से 50 प्रतिशत तक लागत बढ़ा कर उकारते हैं। फिर इंदौर के सेतु संभाग में बैठा भ्रष्ट, जालसाज, भारी शैतान मानसिकता का कार्यपालन यंत्री रा.ना. मिश्रा को बैठाने के बाद शासन यह उम्मीद कर रहा है कि सारे रेलवे ओवर ब्रिज समय पर गुणवत्ता के साथ पूरे हो जाएंगे। जबकि राजेन्द्र नगर ओवर ब्रिज नगर में होने के बाद भी जान बूझकर उसको मंथर गति से केवल कीमतें बढ़ाकर मार्जिन हजम करने के लिए पूर्ण के का.सं. बोरासी ने भी सेतु निर्माणों में किसी में फाउंडेशन का ढाई सेमी मोटी लोहे की प्लेटें नहीं डाली तो बाणगंगा सेतु और अन्य सेतुओं के निर्माण में भी भारी भ्रष्टाचार किया। यहां का स्टाफ भी भारी भ्रष्ट निकम्मा और वर्षों से बैठा भारी जालसाज है। जब सूचना के अधिकारी में जानकारी मांगी गई तो उल्टे-सीधे जवाब देकर टाला गया।

जब अपील लगाई गई तो आखिर ये तो वो भी इन्हीं के अधीक्षण यंत्री को सुनना थी, इंदौर संभाग के बारे में और धार की अपील मे आदेश जानकारी मुफ्त में देने के आदेश भी संभाग के कार्य पं. धार ने और संभाग इंदौर ने भी 6 माह गुजरने के बाद भी इस हरामखोर राणे जिसने कदम-कदम भारी जालसाजी की है। संभाग दो में रहते हुए इंदौर उज्जैन में करोड़ों रुपए हजम करने के बाद पूरी इंदौर से 37 किमी तक को बहुत ही घटिया सड़क बनवाई थी। देवास, धार में रहकर भी इसने हर सड़क में 50 प्रतिशत जमा किया। इंदौर रिंग रोड चौराहे से मांगलिया टोल टैक्स तक प्लेन की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी आधी सी सड़क ये और

इसका महाधूर्त ठेकेदार टीआर गेहन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रालि ने 6 लेन सीमेंट कांक्रीट नहीं कर पाया था परन्तु अक्टूबर 2 की समाप्ती पर 20 प्रतिशत कार्य भी पूरा नहीं किया गया, जबकि यह राष्ट्रीय राजमार्ग एबी रोड का हिस्सा थी। यही हाल रिंग रोड चौराहे दक्षिण से राऊ बायपास तक का भी रहा और अंत में वह समझौता जो कि सांई इंडिया ने किया था समाप्त करना पड़ा, लोक निर्माण विभाग के इस भ्रष्टातार शिरोमणि फिर भी इंदौर में 4 वर्षों से ज्यादा समय से पाला जा रहा है, जिसके पास वर्तमान में रुपए 100 करोड़ से ज्यादा के काम हैं। किसी भी सड़क का काम इस धूर्त ने ढंग से नहीं किया। यही हाल भवनों के निर्माण में भी 10 से 25 प्रतिशत तक घन हजम कर जाता है। जबकि पुताई, मरम्मत आदि का कार्य तो अधिकांश कागजों पर करवाकर ही धन हजम कर जाना इसकी आदत है। बेशक मंत्री नागोद और भ्रष्ट प्रधान सचिव केके सिंह, सचिव और प्रमुख अभियंता अखिलेश अग्रवाल की सेवा पानी अवश्य वे लोग करता रहता है, इसलिए तो सारे धूर्त इसके टुकड़े रखकर इस को यहां पाल रहे हैं।

लो.नि.वि. के विद्युत यांत्रिकीय विभाग में बैठा का.यं. जिसने अपने 20 वर्ष के कार्यकाल में इस का.पं. अशोक बसंल ने अरबों रुपए हजम किए फिर अपने भ्रष्टाचार को दबाने के लिए वर्कचार्ज पर कार्यरत महिलाकर्मी श्रीमती अरुणा के इस धूर्त बंसल ने उच्च वर्ग बाबू का प्रभार दे रखा है। इस बंदी के पास भी दो-तीन मकान हैं। चर्चा है कि इन मकानों का पैसा भी अशोक बंसल की भ्रष्टाचार की कमाई का ही है। इस जालसाजियों का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि तर्क चार्ज की महिला को वरिष्ठ लेखा-लिपिक के बाबुओंको बैठाकर रखा जाता है। ताकि इसके भ्रष्टाचार की कोई सच्चाई कोई न जान सके। वैसे 31 दिसम्बर 12 को सेवानिवृत्त होने वाला है। पूरे म.प्र. में सभी संभागों में चारों तरफ महाभ्रष्ट और निकम्मे इंजीनियरों को बैठाकर किस मुंह से निवेशकों को बुलाकर निवेश कर पाया जा रहा है जो सड़कें भी ओटी में गई हैं। 3 वर्ष के बाद उन पर केवल वसूली ही होती है। सड़कों का रख-रखाव भी ढंग से पूरा नहीं किया जाता, वैसे भी लोनिवि में चारों तरफ भ्रष्टों का जाल फैला हुआ है, जो जन धन की बर्बादी कर अपनी जेबों को भरने में लगे रहते हैं। चाहे वो धार का का.पं. रावत हो, देवास का मंडलोई, उज्जैन का पटेल, बुरहानपुर का आर.के. जोशी, खण्डवा का आरके जैन, खरगोन का आरके जैन, अलीराजपुर का नाइक, झाबुआ का यादव, बड़वानी का पूर्व का उज्जैन का का.पं. अपने भ्रष्टाचार के चलते उज्जैन से हटाकर पदस्थ किए गए, वहीं हाल उज्जैन के अंचल के सभी संभागों जिसमें अलीराजपुर में बंसल, रतलाम का श्रीवास्तव, नीमच में शेट्टे और मंदसौर में उपस्थिति दर्ज कराने वाले का.पं. एसके जैन समीक्षा वर्तमान और इतिहास के संयोग से भविष्य का आकलन किया जा सकता है कि वे किस तरह कार्य कर रहे हैं। सबको भ्रष्टाचार का इतिहास रहा है।

यह तथ्य भी एक कड़वा सच है, अधिकांश कार्य सम्पन्न करने वाले विभागों, जिसमें लोनिवि, लो.स्वा.यां., जल संसाधन ग्रामीण यांत्रिकीय विभागों के साथ अधिकांश राज्य सरकार के विभागों जिसमें कृषि, स्वास्थ्य, महिला बाल विकास आदि में सभी जिलाधीकारियों को सप्ताह के 5-6 दितनों में हर दिन जिला मुख्यालय में कभी वीडियो कांफ्रेंस, कभी टीएलसी, विभागीय मंत्री और प्रधानसचिव, सचिव, आयुक्त, संचालक, ईएनसीकी इतनी मीटिंग्स में उपस्थित होना पड़ता है कि मैदानी क्षेत्रों में जाकर कार्य की गुणवत्ता तो दूर कार्य ही नहीं देख पाते तो जो उनके मातहत अधिकारी कर्मचारी कार्य करते हैं। उसी पर अपने हिस्से की तिकड़म चुपचाप आंखें मीचकर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। अधिकांश विभागों के जिलाधिकारी इन मीटिंग्स से इतने त्रस्त हो जाते हैं कि यर्थाथ के कार्यों जिनके बिचेवे जिम्मेदार कार्य सम्पन्न करने की क्षमता ही नहीं बचती इसलिए आवश्यक है कि जनसुनवाई आदि सभी सप्ताह में तीन दिन से ज्यादा नहीं रखी जानी चाहिए, यह सब भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है।

सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर 6 महीने बाद भी मुफ्त में जानकारी नहीं दी गई और कहने पर उल्ट ही इस धूर्त का.पं. राणे ने ब्लैक मैलिंग का आरोप लगाने लगा, अर्थात ये कुछ भी करे परन्तु इनसे जानकारी न मांगों चाहे मांगलिया से रिंग रोड चौराहे के दो वर्ष में जो काम पूरा होना था तो ढाई वर्ष बाद भी मात्र 20 प्रतिशत ही पूरा हुआ। इस बीच न तो गेहन ठेकेदार ने इस जालसाज के साथ मिलकर सड़कों को मोटरेवल बनाकर रखा, न ही पूरा काम किया। ये राणे का 10 वर्षों का इतिहास रहा है।

(शेष पेज 7 पर)

केन्द्र, राज्य व विदेशी धन के साथ मरीजों से भी वसूली

पेज 3 का शेष

वैसे तो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चाहे तो इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी से लेकर प्रदेश और देश के किसी भी जिले का हो, केवल शासन के प्रदेश, देश और विदेशी धन से जो मिलता है उसका 23 प्रतिशत कमीशन खरीदी में और 25 प्रतिशत खरीदी के बाद बेचने में डकार जाते हैं। 25 प्रतिशत माल खरीदने और आ जाने के बाद बेंचने में कर्मचारी ही डकार जाते हैं। फिर मरीजों से सेचर उठाने से लेकर हर सेवा शुल्क वसूला जाता है, इस लूट खसोट और वसूली से सफाई कर्मचारी वार्ड बाय, नर्स से लेकर डॉक्टर तक सभी शामिल हैं जो अपनी सेवाओं के हिसाब से 25-50 रुपए से लेकर डॉक्टर हजारों तक में वसूली कर लेते हैं। अन्यथा अधिकांश सरकारी डॉक्टर्स शासकीय सेवा संहिता के अनुसार तो 24 घंटे ही शासकीय लोक सेवक है और कोई दूसरा व्यवसाय करने के पास भी नहीं है। इसके विपरित 99 प्रतिशत डॉक्टर्स नर्सेस तकनीशियन जैसे पैथोलॉजिस्ट, रेडियोग्राफर आदि शासकीय सेवाओं के साथ अधिकांश समय या तो स्वयं के निजी संस्थान अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से चलाते हैं या निजी संस्थान में सेवाएं देते हैं। जबकि सभी डॉक्टर्स नॉन प्रेक्टिसिंग भत्ता भी तो है जो स्पष्टतौर पर जनधन के साथ खुली धोखाधड़ी है, पर ये गिद्धों की फौज हर प्रकार से हर जगह, हर कदम वसूली करती है। पर कोई इन जालसाज गिद्धों से कुछ भी नहीं बोल पाता। अब जबकि कांग्रेस सरकार के आने के बाद उस समय तत्कालीन मंत्री अनुमणि रामदास हजारों करोड़ विदेशी कम्पनियों से डकार विश्व स्वास्थ्य बिगाड़ो संगठन जो पूरे यूरोप के राष्ट्रों की बहुराष्ट्रीय कं. के धन चलाई जाती है के इशारे पर पूरे राष्ट्र में सीधे ही बिना किसी को बताए, बिना केन्द्रीय औषधि नियंत्रक और राज्यों के औषधि नियंत्रकों को बताए और बिना आज्ञा के ही औषधि परीक्षण पूरे देश के किसी भी सरकारी निजी चिकित्सालयों में किसी भी मरीज पर भी कैसी भी दवा का औषधि परीक्षण कर रहे हैं। पिछले 7 वर्षों से लगातार बिना किसी पूर्व सूचना मरीज या उसके परीजनों को दिए बिना, हालात यह है कि अब किसी और सरकारी चिकित्सालयों से चिकित्सा के दौरान मरने वाले औषधि परीक्षण के शिकार होते हैं। बरले में डॉक्टरों को करोड़ों रुपए मिलते हैं। विदेशों में किसी भी औषधि परीक्षण को पहले चूहे, फिर खरगोश, फिर शूकरों, बंदरों पर परीक्षण धनात्मक और सफल होने के बाद ही मनुष्यों पर औषधि परीक्षण किए जाते हैं। जबकि हमारे देश में ये औषधि परीक्षण सीधे जानवर रूपी मनुष्यों पर मात्र धन के लालच में कर रहे हैं और करोड़ों रुपए चुपचाप डकार रहे हैं।

हमारे देश में अधिकांश सरकारी सेवाओं में तो भारी नीच प्रकृति के डॉक्टर्स हैं। कुछ तो मानसिक रूप से नीच होने के साथ ही व्यवहार में भी भारी नीच दिखते हैं, जिसमें एक है देवास के सीएमओ विश्नार सूचना के अधिकार में इस जालसाज ने पूरा पैसा जितना कहा गया जमा करने के बाद भी जानकारी तो उपलब्ध 6 महीने भी नहीं दी, साथ ही मिलने की कोशिश भी की गई तो बहुत बत्तमीजी से बातचीत की, फोन पर भी बात करने की कोशिश की गई तो भी बत्तमीजी से पेश आया। जानकारी आवंटन की मांगी तो जालसाज ने कोषालय के भुगतान की प्रतियां उपलब्ध करवा दी। वहीं हाल धार के सीएमओ ने भी किया, जबकि एक सीएमओ के अन्तर्गत 12 विभाग जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, पुनरोत्तादन बाल स्वास्थ, मलेरिया, टीकाकरण, अंधत्व निवारण, कुष्ठ रोग आदि आते हैं। जिनको केवल कागजी जमा खर्च करके झूठे खरीदी और खर्चों के बिल बना कर सारा पैसा हजम किया जा रहा है जो कि करोड़ों में होता है। इसके बारे में ये सारे हरामखोर कभी कोई जानकारी के दस्तावेज आवेदकों को नहीं देते हैं। इसके साथ जननी सुरक्षा, दीनदयाल व अन्य योजनाओं में भी निजी अस्पतालों को भागीदार बनाकर 50-50 प्रतिशत पर सारा पैसा हजम कर लिया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में नियुक्त और वेतन में हिस्सेदारों के दम पर नियुक्तियां की गई। केवल वेतन बांटने के अतिरिक्त सारा पैसा 70 से 80 प्रतिशत हजम किया जा रहा है। अकेले देवास में ही हर वर्ष एनआरएचएम के बजट में जो कि रुपए 13 करोड़ से 15 करोड़ वार्षिक का है, वहां बैठा डॉक्टर मालवीय ही करोड़ रुपए डकार जाता है। बस के कार्यालय में परमिंदर जो प्रबंधक के पद पर है। पिछले 4 वर्ष में इसी लूट खसोट में रुपए 15 से 20 लाख डकार रही है। इसलिए इस बंदी ने कभी भी इस विभाग की स्थापना और नियुक्ति से संबंधित दस्तावेज नहीं मिलने दिए, इस मिशन के आयुक्त रहे तत्कालीन आयुक्त डॉ. मनोहर भगनानी से जो अपनी अय्याशियों के लिए कुख्यात रहे सीधे संबंधों के चलते यहां के भ्रष्टाचारों पर गौर नहीं किया गया, यह हाल इंदौर, उज्जैन, रतलाम, शाजापुर, धार, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, अलीराजपुर जो कि आदिवासी जिले रहे हैं। यहां यह एनआरएचएम, आरसीएम का प्रतिवर्ष रुपए 25 से 40 करोड़ तक धन आता है। यही हाल आदिवासी जिलों मंडला, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, बेतूल, शहडोल, अनुपपूर आदि का भी है, जिसका पात्र-अपात्र केवल उपस्थिति पंजी पर दिखने वाले डॉक्टरों से लेकर आशा कार्यकर्ताओं तक वेतन के अतिरिक्त 70-80 प्रतिशत तक धन डकारा जा रहा है। इस योजना के आने और धन की लूट खसोट की चकाचौंध के चलते स्वास्थ्य विभाग के नियमित डॉक्टरों से वार्ड बाय और नर्सों आदि तक ने अपने कार्यों को धीमी गति के समाचारों में बदल लिया है। ग्रामीणों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सुधार की अपेक्षा बढ़ोत्तरी हो रही है, क्योंकि इसके ठेकों पर संविदा नियुक्ति से आए डॉक्टर्स नर्सें अपनी जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालकर मरीजों को टरकाने और परेशान करते हैं। भ्रष्ट, जालसाज सीएमओ को जिसके अन्तर्गत सभी विभाग है। वर्षभर में रुपए 25-50 करोड़ भ्रष्टाचार की कमाई को पूरा करने में जुटे रहते हैं। उसका कुछ टुकड़ा जिलाधीशों की तरफ भी उछाल दिया जाता है, इसलिए वो रा.प्र.से. से पदोन्नत रुपए 5 करोड़ खर्च करके आए ऐसे जिलाधीशों को केवल कागजी जमा खर्च और उन्नति से मतलब होता है और उनका रुपए 50 से 100 करोड़ का मासिक पूरा मिलता रहे के लाख संधान में जुटे रहते हैं। दूसरी ओर सब ही भ्रष्ट, भ्रष्टन के तू मेरी मत कह, मैं तेरी नहीं कहूंगा, इसलिए सूचना के अधिकार में कैसे दस्तावेज उपलब्ध करवाएं और क्यों करवाए। काहे की अपील, कैसी अपील, तह भी अपील सुनने के अधिकार एसडीएम और एडीएम को सौंप देता हैं, जो गैर कानूनी तरीकों से बिना अनावेदक का अपील पर जवाब भेजे ही सुनवाई का पत्र भेज देता हूं जो समय बाद मिलता है। इस आधार पर संयुक्त संचालक या अपीलीय अधिकारी आवेदक को अनुपस्थित बताकर जालसाज हरामखोर अपील निरस्त कर देते हैं। फिर नीचे से ऊपर तक की कहानी संचालक अशोक शमी, डॉ. मित्तल के रूप में इन्होंने क्या किया पड़ ही चुके हैं। फिर इंदौर के संयुक्त संचालक वर्तमान में बैठे डॉ. शरद पंडित की तो महिमा ही अपरंपार है। 20 वर्ष से इंदौर में बैठे भ्रष्टाचार शिरोमणि यहीं पर ही संयुक्त संचालक भी बना कर पदस्थ कर दिए गए, इतने सारी शिकायतें न्यायालयों में प्रकरण चलने, स्वयं का आशा नर्सिंग होम चलाने शासकीय कर्मचारियों से अपने निजी नर्सिंग होम में सेवाएं लेने, शासन की दवाइयां, मशनें उपयोग करने की शिकायतें होने के बाद भी क्या कोई कुछ बिगाड़ पाया।

साप्ताहिक समय माया

पहले बी.आर.टी.एस. में, आगे मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट में

पेज 1 का शेष

सड़कें बनती हैं और रेती-गिट्टी बिखरने में दो महीने भी नहीं लगते हैं और सड़कों पर जगह-जगह गड्ढे हो जाते हैं। गिट्टी और चूरी बिखर जाती है। सड़क बनाने वाली ठेकेदार कं. और इं.वि.प्रा. व निगम के इंजीनियर हरामखोर कहने भर के इंजीनियर्स है, जिन्हें केवल कमीशन से मतलब है, इन निकम्मे शूकरों ने कैसा और क्या प्रोजेक्ट बनाया कि सड़कों पर बरसाती पानी को निकालने तक की व्यवस्था नहीं थी किसी अंगूठा छाप अनपढ़ से भी पूछो तो कहेगा कि सड़कों के दोनों तरफ पहले जल निकासी की व्यवस्था करें, फिर 10-10 कि.मी. लंबी सीमेंट की 100-200 चौड़ी सड़कों के बाजु से 3'' से 5''चौड़ी, 3 से 5 गहरी खाली नाली हर 500 मी. पर सक क्रास करती नीचे पुलिया भी बनाओ ताकि भविष्य में गैस पाइप लाइन, केबल लाइन, विद्युत लाइन, जल के पाइप बिछाने, सड़कों को क्रॉस करने में फिर से सड़कें न खोदना पड़े और यातायात बाधित न करना पड़े। हर दो-तीन कि.मी. के बाद बीच सड़क पर जो बसों के लिये स्टेण्ड बनाये जा रहे हैं पूर्णतः बकवास और पैसे की बर्बादी सिद्ध होंगे, पर कं. और इंजीनियरों दोनों को खर्च दिखाकर हजम करने की लत लगी है। उनकी बला से कोई उपयोग हो न हो, सभी को मोटा कमीशन चाहिये। इसलिए दोनों तरफ खतरनाक नौकदार दोनों तरफ लोहे की मोटी जाली लगाई गई है, जिसके बनते समय ही दो और चार पहिया वाहन चालक दुर्घटनाओं के शिकार होकर घायल हो चुके हैं। जैसे सड़कों पर जनता नहीं जंगली जानवर उसका उपयवोग करेंगे या जनता नहीं वो दुश्मनों की फौज का रोकने के लिये लगाई जा रही हो, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य करोड़ों रु. बर्बाद करने बाद शायद समझ आयेगा तब तक कमीशन हजम हो ही जायेगा, हमारे राष्ट्र में बायें चलने का नियम है, इसलिये सारे बस स्टॉफ बायें तरफ ही बनाये जाते हैं। जबकि बीआरटीएस में ये बीच में जो प्लेटफार्म बनाये जा रहे हैं। जबकि बायें चलने के नियम के कारण सारी बसों में दरवाजे में बायीं तरफ ही लगाये जाते हैं। और अटल बसों में भी सारे बायें तरफ ही हैं। तो दायीं तरफ से प्लेटफार्म से खिहकियों से यात्री बसों में आयेंगे जायेंगे क्या? ये इंजीनियर्स आईडीए और नगर निगम ने जो नक्शे बनायें हैं क्या सोचकर बनाये गये। यह आम आदमी की समझ से ही परे हैं। दूसरी ओर निगम और प्राधिकरण के इंजीनियर्स ठेकेदार कं. के साथ मिलकर जानबूझकर धीरे-धीरे बना और बनवा रहे हैं ताकि बढ़ी हुई कीमतों का लाभ लिया जा सके, इस प्रकार ये बीआरटीएस का कार्य सन् 2015 तक भी पूरा नहीं होगा और लागत सीमेंट सरिये व मजदूरी आदि की दोगुनी हो जायेगी तो कमीशन भी दोगुना मिलेगा जब तक 100-200 इन गड्ढों में तारों में, रिबन की फेसिंग में गिर कर मर चुके होंगे।

अब मोटा कमीशन डकारने के लिये रु. 8000 करोड़ का मेट्रो ट्रेन का प्रोजेक्ट भी लाया जा रहा है। जिसकी अवधि होगी 5 वर्ष, जबकि ये 2030 तक भी पूरा हो जाये तो भी वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी का सौभाग्य होगा। तब तक 3 विधानसभाओं के चुनाव हो चुके होंगे हर नेता के लिये ये मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट दुधारु गाय होगा। जैसे कि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के बांध, डूब, क्षतिपूर्ति, विस्थापितों का पुर्नवास को लेकर 1980 से सन् 2012 तक हर सरकार के लिये कामधेनु गाय सिद्ध हो रहा है वैसे ही इसलिये मेट्रो ट्रेन के निर्माण कार्य भी 5 वर्ष से बढ़कर 15 वर्ष में भी पूरे नहीं होंगे और सड़कें, कालोनियां, बस्तियां खुदी, उखड़ी और बिखरी पड़ी रहेगी और रु. 8000 करोड़ की परियोजना लागत भी रु. 24000 करोड़ हो जायेगी। हर सरकार के मंत्री, नेताओं, केन्द्र व राज्य सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों के लिये दूध धोने वाली गाय ही सिद्ध होगी।

इस इतने बड़ी परियोजना में भी परेशानी होगी तो आम आदमी को। जब तक 100-200 आम आदमी, 25-50 काम करने वालों की मौतें होंगी, घायलों की संख्या तो कुछ भी हो सकती हैं, फिर भूतल के नीचे या जमीन से 30' ऊपर पटरी बिछाई जायेंगी तो शहर तो खोदना ही पड़ेगा आखिर रु. 8000 करोड़ का काम भी दिखाना पड़ेगा। जिसमें रु. 4000 करोड़ की बंदरबांट तो अवश्य संभावी होगी।

हर कदम दो मुंहा-कथनी कुछ, करनी कुछ

पेज 1 का शेष

दोहरे को चार और छह लेन सड़कों के बनाने में ही रुपए 7000 करोड़ का न केवल गच्चा दिया वरन् सड़क किनारे के बड़े पहाड़ों को काटकर और छोटी-छोटी पहाड़ियों को साफ कर पर्यावरण चक्र ही बिगाड़ दिया जबकि म.प्र. की धरती से कोयला. अभ्रक, तांबा, लोहा एल्युमिनियम से लेकर हीरा-पन्ना तक वर्षों से निकाला जाकर हर वर्ष रुपए 1 लाख करोड़ से ज्यादा के राजस्व की चोरों में स्वयं खनन माफिया के साथ जिलाधीश कार्यालय खनन विभाग से लेकर मंत्री राजेन्द्र शुक्ला, तक व अन्य मंत्री व ने हामी शामिल होकर हरामखोर डकैतों की फौज अरबों की कमाई कर रही है, जिसमें हाल में पड़े छापों में सुधीर शर्मा और दिलीप सूर्यवंशी जैसे खनन और निर्माण ठेकेदारों के नाम भी आए परन्तु खनिज विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की उन्हें क्लीनचिट दे दी गई। मुरैना में आईपीएस की हत्या कर दी गई, चार दिन शासन, प्रशासन और नेताओं ने हल्ला मचाया पर फिर लूट खसौट अवैध खनन का कार्य पूरे प्रदेश में पूरे जोरशोर से पूरे प्रदेश चल रहा है। जब ज्यादा हल्ला मचता है तो मुमं. शिव केवल मुंह चलाकर फूंफकार चुप हो जाता है। क्योंकि हिस्सा तो हजारों करोड़ों का मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच रहा होता है। कैसे कोई कार्यवाही करे ये है ईमानदारी। निष्पक्ष कार्यवाहियों का आश्वासन क्या हुआ आईपीएस अधिकारी की हत्या जो शिवराज के स्वच्छ प्रशासन के माथे का कलंक बन गई पूरे देश में सीबीआई ने भी क्या कर लिया सारे न केवल खुले घूम रहे हैं। वरन् श्योपुर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड में एडीएम एसडीएम के ऊपर भी हमला कर खुले में चिल्लाते हैं कि जब हम आईपीएस को निपटा सकते हैं तो एडीएम, एसडीएम कि क्या औकात है। ये है काननू का गुंडाराज मप्र में अब चूंकि स्वयं खनिज मंत्री राजेन्द्र शुक्ल खुद रीवा का बड़ा खनन माफिया है तो फिर दूसरे खनन माफियाओं, लोनिवि, म.प्र. सविनि, रा.रा.मा.प्रा. व सभी निजी निर्माण भूमाफियाओं, कोल माफिया, बावसाइट, भूमाफिया से लेकर हीरे-पन्ने के अवैध खनन और चोरी को कौन रोकेगा। हमारा नौटंकीबाद शिव मु.मं. भ्रष्टाचार की मंडियां जो हजारों करोड़ में होती है। पीकर इंवेस्टरर्स मीट इसलिए करवा रहा है ताकि अपना काला धन, यदि उद्योग चले और अनध लाभांश कमाए और दें तो ये भी, लाखों करोड़ में निवेशित कर सकें।

यही हाल म.प्र. लोक निर्माण विभाग का भी है, यहां लोक नि.वि. संभाग क्र. 1 में बैठा राणे जिसने 4 वर्ष से ज्यादा इंदौर में पूरे कर लिए महाभ्रष्ट का.यं. राणे जिसने मालवा में कदम रखते ही भारी लूट पाट मचा रखी है, इसने देवास संभाग में भी हर काम में 25 से 40 प्रतिशत वही हाल धार संभाग में किया जब चारों तरफ भारी शिकायतें और भ्रष्टाचार के मामले सामने आए तो अपने ग्वालियरी आका नरेन्द्रसिंह तोमर के माध्यम से अपनी पकड़ के चलते इंदौर के संभाग के 2, अंबेडकर नगर भवन महू में खरीदी में भ्रष्टाचार के चलते लगी लोकायुक्त जांच के बाद भी उसे संभाग क्र. 1 में पदस्थ कर दिया गया, जबकि महू और सांवेर में इंदौर-सांवेर-उज्जैन सड़क में काफी भ्रष्टाचार के कारण सड़क पर जो कि इंदौर से 37 किमी तक उसका पुर्ननवीनीकरण का पैसा हडम करके उस पर पेंच वर्क करवाकर हल्का से पोता लगाकर छोड़ दिया गया था, के भ्रष्टाचार के मामले भी काफी समाचार पत्रों में छपे। अब जबकि पं. राणे को संभाग क्र. 1 में भी काफी समय हो जाने के बाद और उसके हर कार्य, जिसमें रिंग रोड चौराहे से मांगलिया बायपास तक की 6 लेन सड़क निर्माण में 2 वर्ष का समय समाप्त होने के बाद भी कार्य अधूरा है। वहीं हाल पिगडम्बर से राऊ पास के एबी रोड की सड़क का भी है, जब एबी रोड के ये हाल है। इंदौर-महू तहसील की अनेकों सड़कों के कार्य और गुणवत्ता का अंदाज, समाचार पत्रों में छपी अनेकों सड़कोह की बर्बादी से लगाया जा सकता है और हमारे मु.मं. शिवराज ऐसे भ्रष्टों को पालकर इंदौर में 28 अक्टूर तक वैश्विक निवेशक का आयोजन भी इंदौर में ही कर रहे हैं। जबकि इंदौर में चारों तरफ इस जालसाज मु.मं. ने चुन-चुनकर म.प्र. के बड़े भ्रष्टों, कलेक्टर आकाश त्रिपाठी, आयुक्त प्रभात पारासर, जिला पंचायत में मु.का. अधि. गोपाल डांड, निगमायुक्त, एसएसपी सांई मनोहर, एसपी, आईजी तक। फिर म.प्र. औद्योगिक केन्द्रीय विकास निगम का भ्रष्ट जालसाजों से भरा स्टाफ एमडी तक, ऐसे शूकरों की फौज वर्षों से कुंडली मारे बैठी है, जो इस दो मुंहे की 28 से 30 तक सम्मेलन समाप्त होते ही अपनी नोच खसोट के कारण पूरी भ्रष्टाचार पूर्णचरित्र के चलते कदम-कदम पर वसूली वास्तविकता का वर्णन कर देगी, पूर्व की तरह लाखों करोड़ के निवेशक थकहार कर मुंह चिढ़ाकर रुपए 1000 करोड़ का निवेश भी नहीं करेंगे।

मु.मं. मंचों पर चढ़कर तो अपनी तारीफ के बड़े-बड़े पुल बांधता है, जनता के हितों की बातें करता है। जन धन की बर्बादी करते हुए मीडिया का मुंह बंद रखने के लिए अरबों रुपयों के विज्ञापन छापता है, पर यहां मुख्य सचिव आर. परशुराम ही महाभ्रष्ट और जालसाज है, जिसने ग्रामीण विकास प्र.स. रहते हुए ही अपने और अपने मंत्रालयों जिसमें पंचायत, ग्रामीण विकास आदि के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जो पहले लोक सूचना अधिकारी था। उसका अपीली अधिकारी जिलाधीश था, जिला पंचायतों में ही सारे जिले, जनपद पंचायतों, सैकड़ों ग्राम पंचायतों का हर वर्ष करीब विभिन्न योजनाओं में रुपए 1200 करोड़ से आदिवासियों में रुपए 4 से 5000 करोड़ तक केन्द्र व राज्य का धन आता है, जिसमें रुपए 80 से 150 करोड़ का नरेगा, रुपए 15 से 25 करोड़ का मध्यान्न भोजन, महिला बाल विकास, ग्रामीण विकास राजीव गांधी जल ग्रहण मिशन, निःशक्त विधवा पेंशन, मु.मं., प्र.मं. आवास आदि योजना, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना स्व रोजगार योजना है, आदि से संबंधित 32 करोड़ पुस्तकें न्यूनतम लिखी जाती हैं कि जानकारी सूचना के अधिकार में न देनी पड़े इसलिए जिला पंचायतों से अब बानु स्तर का लोक सूचना अधिकारी और स्वयं मु.का. अधि. को अपीलीय अधिकारी बना दिया गया, जिला पंचायत में बैठे वर्षों से जमे अजगरों की फौज पहले तो पत्र ही नहीं लेती, यदि पत्र ले भी लेती है तो लाखों का बिल आवेदक को डसने के लिए दे देगी। यदि आवेदक जानकार हुआ तो उसकी अपील करेगा, जिसे मु.का.अधि. शब्दों के जाल में उलझाकर रद्द कर देगा, यही हाल वर्तमान मु.स. परशुराम ने ग्रामीण यांत्रिकी विभाग में किया अब अपीतीय अधिकारी स्वयं कार्यपालन यंत्री ही होता है और उसका बाबू लो. सूचना अधिकारी, मुख्य सचिव बनने के बाद इस शूकर ने यही जालसाजी वन विभाग में भी की।

जन मुख्य सचिव ही इस बिरथे दर्जे का जालसाज बैठाया गया हो तो बाकी सारे इंडियन एब्यूसिंग सर्विस के अधिकारियों की तो भ्रष्टाचार और जालसाजी करने की उन्मुक्तकरण प्राप्त कर भारी खुश होंगे है। अब चाहे लोनिवि,लो.स्वा. यांत्रिकी, स्वास्थ्य ग्रह परिवहन, आबकारी, सारे प्रदेश के जिलाधीशों से लेकर पटवारी तक सब लूट खसोट में जुटे हुए हैं।

ऊपर से भुखेरे से मंत्रियों की फौज, जिनके लूट भ्रष्टाचार, जालसाजियों के कांड पूरे प्रदेश के समाचार पत्रों में छाए रहते हैं। शिवराज के मंत्री मंडल में कौन सा मंत्री है, जो भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त न हो। फिर भी ईमानदारी की बातें करना, इसकी तारीफ में भाजपा इसकी दो मुंही बातों का पथार्थ पाठक स्वयं समझ सकते हैं।

फिर एक तरफ दिखावे के लिए एफडीआई का विरोध दूसरी तरफ पूंजीपतियों, उद्योगपतियों के ईशारे पर नाचकर और मोटा धन हजम कर सरकारी सम्पत्तियों, यथावो ओटी के अन्तर्गत राष्ट्रीय राज्य मार्ग उन्हें दे दिए गए। अब ये भी ओटी के श्वान वाहन चालकों को लूटते भी हैं और सड़कों की दयनीय हालत देखी जा सकती है। उज्जैन झालावाड़ मार्ग जहां पाथ का पुनीत अग्रवाल वसूली भी पूरी बढ़ा चढ़ाकर कर रहा है। जबकि सड़कों सील कोट तो दूर पेंच वर्क भी ढंग से नहीं किए जा रहे, दूसरी ओर मालवा क्षेत्र की दो अन्तरराज्यीय सड़कों जो म.प्र. रोड डकैत कार्य के पास है, जिसमें एक तो बिना फोरलेन के उस पर टोल टैक्स वसूल किया जा रहा है। दूसरी ओर उन दोनों ही सड़कों पर यातायात का भी दबाव है, तीसरी तरफ सड़कों को 5 वर्ष से ज्यादा हो जाने के बाद भी दोनों ही डकैत ठेकेदार उज्जैन-कोटा में शैलेन्द्र अग्रवाल का अग्रोहा इस्फ्राक्ट्रक्चर, जो इंदौर से इच्छापुर 203 किमी जदो आगे भुसावल तक जाता है। इन जालसाज ठेकेदारों ने वसूली तो हर वर्ष 7 प्रतिशत से बढ़ा कर ही कर रहे हैं।पर दो लेन अर्थात 27 फूट के दोनों तरफ अभी तक सड़क से मिलकर 5-5 की कच्ची मुरम से पट्टियों नहीं भरी गई, यही हाल पूरे प्रदेश की सड़कों के होने के बाद मीवंदा चूकि पूरे प्रदेश के ठेकेदारों से वसूली में अपना हिस्सा वसूल कर रहा है। इसलिए जानबूझकर सड़कों की दयनीय दशा होने के बाद भी रा.रा. को अपने कारनामों को ढंकने के लिए अवश्य कोसता है, जबकि जो स्वयं के पास अधिकांश सड़क होने के बाद भी उस पर वसूली अर्थात वाहन चालकों से लूट और वसूली के बाद भी सुविधाएं नहीं तो क्यों जनता को लुप्ताया जा रहा है। फिर क्यों निवेशकों आकर्षित करने के ढोंग रच रहा है।

वहीं हाल बिजली आपूर्ति का भी है जो इन हरामखोर जालसाज के बारे में लिखा गया था, कि ये हरामखोर मोटा कमीशन खाने के लिए हर वर्ष में दो बार बिजली की कीमतें बढ़ा रहे हैं। फिर भी आपूर्ति के लिए जनता को रुला रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ म.प्र. विद्युत मंडल तारणी, वीरसिंहपुर के संजय गांधी के सारे ताम विद्युत इकाइयां जानबूझकर खरीदी में मोटा डकारने के लिए बंद कर दी, फिर कमी दिखा कर कटौती और फिर निजी कम्पनियों से कोयला घोटाला करके महंगी बिजली खरीदी कर रहे हैं। उज्जैन जैसे अनेकों शहरों में निजी कम्पनियों को जनता को लूटवाने के लिए कमीशन डकार कर फेंचायजी बांटी जा रही है। तो निजी कम्पनियां सबसे पहले पूरे उज्जैन जिले के दोगुनी तेजी से चलने वाले भीतर लगा कर चौगुने पैसे वसूलेगी, जिसमें इस शूकर शिवराज का भी कमीशन होगा, ये है निजीकरण करवाकर डकैती का दास्तां।

यही हाल पूरे प्रदेश के हर विभाग का है, मप्र वि.मं., सड़के अब पानी का भी निजीकरण करके लूटेंगे ये सत्ता के डकैत। इतनी सारी हर कदम लूट, डकैती और जालसाजियां करने के बाद मु.मं. शिवराज अब अपने आप को शहंशाह समझने लगा है। वह सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को भी अपनी पीछे की जेब में लेकर चल रहा है। साथ ही उनका मुख्य सचिवर परशुराम ने भी स्पष्ट कह दिया कि हम सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को कोई भी मान्यता नहीं देते हम उससे भी ऊपर हैं। हम विभागीय पदोन्नतियों देते रहे है और देते रहेंगे। ये है इस दोमुंहे की कानूनी सत्ता, कानून का पालन हो रहा है। सबसे वाड्रा चुने गए प्रतिनिधि को वैसे ये महा भण्डार, जालसाज, मुख्य सचिव और प्रधान सचिव जैसा टांकते बजाते हैं। वैसी ही मुख्यमंत्री और मंत्रीगण चलते और नाचते हैं।

पेंशन, बीमा व्यवसाय में क्या जरूरत है, विदेशी निवेश की

पेज 1 का शेष

सत्ता में आते ही इस धूर्त मनमोहनसिंह ने जिस खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि. 06 को लागू किया था, उसके अध्ययन के निष्कर्षों को समय माया ने जो प्रकाशित किए थे, वे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा बढ़ाकर 51 प्रतिशत से सिद्ध हो गए उस पर दलील ये कि वो रुपए 13000 करोड़ निवेशित करेंगे तो दान करने के लिए नहीं वरन रु 1 लाख व 30 हजार कमाने के लिए रु 2 के आलू चिप्स रुपए 20 में बेचे जा रहे हैं। रुपए 2 व 3 प्रति कि. गरीबी रेखा का गेहूं रु. 20 प्रति किलो के आटे के पैकेट में बेचा जा रहा है, जिसमें आई हो सी रिलायंस पारले से लेकर टाटा, वालमार्ट का ईजी डे भी बेच रहा है। ये सारी बहुराष्ट्रीय कं. का मूल उद्देश्य है छोटे दुकानदारों, विक्रेताओं और उत्पादकों को समाप्त करो और एकाधिकार कर रु. का माल दुगुने से लेकर 100 और 1000 गुनी की मत पर बैचो। देश की आम जनता नोचों, कहां जाएगी। जनता महंगा मिलेगा तो भी खाएगी जनता, इन सत्ताधिशों को तो हर माह इन बहुराष्ट्रीय कं. से मोटा कमीशन मिल ही जाएगा, छोटा उत्पादक, विक्रेता, दुकानदार जो करोड़ों में है, कुछ भी नहीं पहुंचाते। इन भुखेरे गिद्धे नेताओं मंत्रियों को फिर सत्ताधीशों को मालूम है, उनकी औकात 5 वर्ष है। जितना लूट सकते है, जैसे लूट सकते हैं। कानून बनाकर ऋण लेकर, पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतें बढ़ाकर देश के व्यापार, उद्योगों के बर्बाद कर, संचार सीमा, बैंकिंग, विद्युत, पेंशन, खनिज, जल, वायु, सबको गिरवी रख कर अपने विदेशी खातों में भरो, जमा करो, न जाने फिर कभी मौका मिला नहीं मिला। यही कारण था कि बीमा और पेंशन में 49 प्रतिशत तक विदेश निवेश की छूट दी गई, जबकि पूरा बीमा व्यवसाय भय वसूली और जालसाजी का व्यवसाय जहां 95 प्रतिशत वसूली होती है और 5 प्रतिशत क्षतिपूर्ति, पर 3 प्रतिशत क्षतिपूर्ति देने में भी सैकड़ों नियम कानून लगाकर डकारने और बीमित को क्षतिपूर्ति न देने की कोशिश की जाती है।

ये है निजी क्षेत्र की बीमा कं. की वास्तविकता, प्रीमियम लेते समय तो ये हरामखोर एजेंटों की फौज लंबे-चौथे वायदे करती है और जब 5% भी क्षतिपूर्ति देने का दायित्व सिर आता है, तो फिर कदम-कदम सैकड़ों नियमों-कानूनों का जाल बिछाकर उलझाया जाता है, सैकड़ों चक्कर लगवाने के बाद भी क्षतिपूर्ति के नाम ढेंगा दिखा दिया जाता हैं। 0.5% लोग ही जो बीमित होते हैं जीवन बीमा व वस्तु बीमे के लिये उपभोक्ता फोरम की शरण लेकर लड़ाई लड़ते हैं। उसमें भी न्यायालयों की तरह पेशियों पर चक्कर लगाने पड़ते हैं। अर्थात भारत में कार्यरत अधिकांश बीमा कं. जिसमें रिलायंस, इफ्को, टोक्यो, बजाज एलांयज, मेक्स आदि जिनके नाम चल रहे हैं। वर्तमान में उनकी स्थिति देखने के बाद भी यह निर्णय लेना केवल कमीशनखोरी की लालसा का ही परिणाम है।

अब पेंशन में 51% विदेशी निवेश की क्या जरूरत थी जबकि उसमें पहले से केन्द्र और राज्यों का अरबों रु. के प्रबंधन तो ढंग से हो नहीं पा रहा उस पर भी जब देखो सरकार उसके ब्याज की दरें घटाती रहती है, इसलिये ताकि उसके भार को सरकार कम कर सके, जबकि अधिकांश शासकीय विभाग का निजीकरण करने पर तुली है सरकार।

शासकीय कर्मचारियों के जीवन भर की कमाई का धन 30-40 वर्ष उपयोग करती हैं सरकार। यदि पेंशन में 51% निवेश की छूट दी जा रही है, तो अरबों रु. का कमीशन डकार जानबूझकर पेंशन फंड जिसमें एक पैसे के निवेश की जरूरत ही नहीं थी, आखिर 51% निवेश करवा कर वह जो पैसा विदेशी निवेश करेंगे वो किस में, किसलिए करेंगे, कुल अंत में कहानी जो सामने आयेगी तो सारे पैसे पर कब्जा करके उल्टे-सीधे निवेश दिखो करोड़ों बुजुर्गों का धन विदेश भेजकर दिवाला निकालकर पेंशन निधि भी चट करके भाग जायेंगे। बाद में करोड़ों सेवानिवृत्त बुजुर्ग दो वक्त की रोटी के लिये तरस कर मृत्यु को प्राप्त हो जायेंगे। सरकार में बैठे सत्ताधीश और विदेशी निवेशक भी यही चाहते हैं कि किसी प्रकार पेंशन निधि जो लाखों करोड़ में हजम कर ली जाये और पेंशनर्स को कम से कम भुगतान देना पड़े, फिर पेंशनर्स चाहे भूख-प्यास, दवाओं के अभाव में बीमारी से मरे या स्वयं विषपान करके मर जायें, यदि विदेशी 25% डकारेंगे तो पेंशन निधि का 75% ये हरामखोर शूकरों की फौज डकार जायेगी नाम करेगी कि विदेशी लेकर भाग गये।

इटालियन सोनिया राष्ट्रीय संपत्तियों को विदेशियों के हवाले कर रही है धीरे-धीरे इसके लिए पहले बाकायदा कानून बनाये जाते हैं, फिर माहौल, मीडिया के भुखेरे गिद्धों को टुकड़े डाले जाते हैं। जनता को भ्रमित करने दृश्य, श्रव्य और मुद्रित माध्यमों से उसकी चकाचौंध दिखायी जाती हैं, फिर अपने बाप की जागीर समझ ये नीच मानसिकता के भुखेरे सत्ताधीश भेड़िये पहले चिलाते हैं कि पेट्रोल, केरोसीन, डीजल, गैस पर सरकार अनुदान देती है, जैसे वह अनुदान इन शूकरों के स्विस खातों से दान में आ रहा हो, इस बहाने अपने पूंजीपति आकाओं रिलायंस की जामनगर रिफायनरी से मोटा लाखों करोड़ कमीशन डकार कर उसे अरबों-करोड़ का फायदा पहुंचाते हुए उसी से क्रय किया जाता है, इस प्रकार महंगाई बढ़ाकर लूटा जाता है।

जनता और मीडिया का ध्यान बंटाकर उसकी आड़ में ये राक्षसों की फौज राष्ट्र व जनधन को बेचने गिरवी रखकर लाखों करोड़ का खेल खेलती रहती हैं। इनके 99% जालसाजियां तो सामने ही नहीं आती हैं जो सामने आती हैं वो मात्र इनकी कारगुजारियों का 0.5% से 1% भी नहीं होतीं।

ओबामा, हिलेरी से रोमांस करे

पृष्ठ 1 का शेष

बहुराष्ट्रीय और अरबों डॉलर की बड़ी निर्माण सेवा प्रदाता कं. अपने कार्य होने और लाभ मिलने तक लोगों को रोजगार देंगी, बेहतर होता कि विद्युत, संचार सेवायें, रेलें और बैंकिंग को राष्ट्रीयकृत कर देते, ताकि बेरोजगारों को बेहतर रोजगार मिलता और उसका लाभ राष्ट्रीय लाभ होता, माल कल्चर अर्थव्यवस्था को कचरा देती है, जो आपके सामने हैं, एशियाई राष्ट्रों में जनसंख्या ज्यादा होने पर भी उस तुलना में लोग ज्यादा भूखे नहीं मरते हैं। भारत में गांधी का कहना था कि ज्यादा लघु और कुटीर उद्योग ज्यादा लोगों को रोजगार, परन्तु न केवल अमेरिका को बहुराष्ट्रीय कं. और माल कल्चर ने बर्बाद किया वरन् भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिये उठाये भारत के भ्रष्ट प्रधानमंत्री और मंत्रियों को खरीद कर मालकल्चर को बढ़ावा देने के लिये उल्टे ही दबाव डाल रहे हो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीपति हर तरह से जनता और कर्मचारियों का शोषण करते हैं। बेहतर होगा कि भारत जैसे देश में पूंजीवाद को विकसित करने की अपेक्षा अपने देशके पूंजीपतियों के बड़े-बड़े उद्योगों को राष्ट्रीयकृत करके उस पूंजी को राष्ट्रीय हित में लगा दो, पर शायद यह सोचने और समझने की फुर्सत तो तब मिलेगी जब पूर्व राष्ट्रपति की बीवी और अपनी विदेशमंत्री के रोमांस का जुनून दिमाग से दूर होगा, विश्व पर दादागिरी और गुंगडागर्दी का अमेरिकी जुनून, एशियाई राष्ट्रों में अपने हथियार बेचने के लिये आतंकवाद को बढ़ावा देने का जुनून, पेट्रो राष्ट्रों के पेट्रोल पर कब्जा करने के लिये षड्यंत्रों की तैयारी फिर युद्ध थोपने का जुनून ठंडा पड़े, तो राष्ट्र की वास्तविक समस्यायें चीन, जापान और अन्य यूरोपीय देशों से कर्ज उतारने, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की बात और तथ्यों पर अमल किया जा सके, विश्व पर अपनी बादशाहत कायम रखने के और भी बहुत से तरीके हैं। अमेरिकी जनता ज्यादा शिक्षित है, आन-बान-शान से रहने के लिये कर्ज लेकर घी पीना उसे ही आता है, इसके साथ ही उसको न केवल अपने बेहतर भविष्य की चिंता भी सताती है, इसलिये जनता को चाहिये कि वो पहले रोमांस में उलझे राष्ट्रपति को न चुने, दूसरी ओर पूंजीवाद का बहिष्कार करें और अमेरिकी प्रशासन पर दबाव डालकर मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू करवाने की व्यवस्था करें, दूसरे देशों पर अपना वर्चस्व स्थापित करने, उन पर दबाव बनाने और आक्रमण करने की नीति को 10-20 वर्ष तक जब तक कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था पटरी पर न आ जाये, सोचे भी नहीं, अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कं. के लिये युद्ध भी एक व्यवसाय है जिसमें हथियारों के सौदागरों से लेकर युद्धक पनडुब्बियों, जहाजों, विमान वाहन पोतों, बमवर्षक, जासूसी विमानों आदि का निर्माण, बिक्री आदि के लिये उन्हें युद्ध करवाना जरूरी है। विश्व के जिन 90 से ज्यादा देशों में अमेरिकी सेनायें पड़ी हैं। जिसमें जापान, ईराक, अफगानिस्तान जैसे राष्ट्र शामिल हैं। अपनी सेनाओं और उनके खर्चों में कटौती करें, इसके लिये आवश्यक है कि नई सोच वाला राष्ट्रपति हो, जो शासन-प्रशासन पर ध्यान दें, पुनः यदि ओबामा को चुना गया तो अगले 4 वर्ष में अमेरिका रसातल में पहुंच जायेगा।

विज्ञापनों में फंसने से पूर्व जाने समझें, घटी दरें

पेज 8 का शेष

2 कैरेट अर्थात 48 प्रतिशत का सोना भी नहीं होता और ग्राहकों से कीमत पूरी 96 प्रतिशत स्वर्ण की वसूली जाती है। बीआईएस हॉलमार्क जो शास. संस्थान है। उन्हें महीना पहुंचाते रहे तो 100 प्रतिशत तांबे पर भी स्वर्ण की मुहर लगाने से नहीं चूकेंगे अर्थात हॉलमार्क की आईएसआई संस्थाओं में इंसान बैठते हैं। तो भी लोभ-लालच, भ्रष्टाचार के पुतले ही होते हैं वो भी बिकते हैं। महीना आते हैं फिर स्वर्ण का 1 ग्राम भी रुपए 3000 का होता है। जेवर बनाने के बहाने टांका लगाने के बहाने यदि 25 से 50 प्रतिशत भी मिलावट करके बेंचते भी कौन पकड़ लेता है उन्हें। फिर स्वर्ण भूषण बेंचने वाला कोई ईमानदार तो होता नहीं चाहे उसका कालाधन संभालने में ही उन्हें कहीं हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर खोलकर चलाते हैं कहीं फैक्ट्रियों में तो कहीं जमीनों में धन लगाते हैं कमाते तो जनता को लूटकर ही हैं। सभी उच्च मध्यम वर्गीय और उच्च वर्ग दीपावली पर स्वर्ण भूषणों में दिल खोलकर निवेश करता है, यही कारण है कि सभी नगरों, महानगरों के सराफा बाजार धन तेरस पर आधी रात तक बिक्री करते हैं।

वस्त्रों, बर्तनों, रंग पेंट, फटाकों से लेकर मिठाई तक बिक्रेता को अपने माल की श्रेष्ठता बताकर, माल बेंचता है। यह क्रेता का कर्तव्य है कि वह धन खर्च करते समय उसकी सत्यता को परख कर अच्छाई बुराई आंकलन की धन निवेशित करें। इलेक्ट्रानिक गुड्स यथा मोबाइल, लेपटॉप, कम्प्यूटर्स, टबस, एलईडी, टीवी, विजिलेंस, कैमरे, वीडियो कैमरे आदि का ब्रांड दूसरे उपभोक्ता के विचार अनुमत, गारंटी-वारंटी, उसको चलाने के साफ्टवेयर उसकी सर्विसिंग, कीमतों का तुलनात्मक अध्ययन जो अब हर कम्पनी की साइट्स पर भी उपलब्ध है। ऑनलाइन खरीद-बिक्री में आपके डेबिड कार्ड, क्रेडिट कार्ड के नं. व कोड कम्प्यूटर्स के माध्यम से ऑनलाइन होने के कारण हैकर्स के जालसाजों द्वारा चुराए जाने और उसमें से भुगतान निकालने के खतरे विश्वत स्तर पर सदा ही बने रहते हैं। खाता धारकों को मालूम ही नहीं चलता कि कब उनके खातों से दुनिया के किस से पैसा निकाल लिया गया। बेहतर है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक खरीदा जाए सामने देख परखकर ही खरीदा जाए। उपभोक्ता और जनता को चाहिए कि किसी भी छूट की लूट में जाने से पहले या खरीददारी माल की वास्तविकता अच्छी तरह जांच परख लें अन्यथा बाद में पछताना न पड़े।

सूचना के अधि. में जानकारी मांगने पर करते हैं जालसाजियां

पेज 5 का शेष

दूसरी ओर इनका ही शिष्य जो का.पं. संभाग क्र. 2 था को सूचना के अधिकार में जानकारी के लिए पत्र दिया तो वंदे बागोले ने समय बाधित होने के बाद पत्र का जवाब दिया, उसके 30 दिन के उपरांत जब उसमें अपील की गई तो का.पं. बागोले के साथ उनके स्टाफ ने पहले तो दबाव बनाया कि लिखकर दे दो कि हमने जानकारी देख ली है। जब श्री अजमेरा ने मनाकर दिया तो बोलने लगे कि मि. अजमेरा आपने अपने हाथ से प्राप्ति की सील लगाई है। उसमें सुमदा शुक्ला लिख दिया है। जब श्री अजमेरा ने बोला कि चलिए मामला न्यायालय में ले चलते हैं।

यदि मैंने जालसाजी करके सील लगाकर प्रगति पर सुमदा शुक्ला लिख दिया है तो मुझे जेल भेज देगा नहीं तो आपकी नौकरी छोड़ देना, जब बात यहां तक बढ़ी तो बोलने लगे कि मैं उस मैडम को शोकाज नोटिस जारी करके उसकी नौकरी चाहूंगा अर्थात ये कुछ भी करे। आप जानकारी मांगेगे तो ये जालसाजी करेंगे।

ये तथ्य से स्पष्ट करते हैं कि ये पूरे लोक निर्माण विभाग का.पं. किस प्रकार और कितने हद तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं कि सूचना कि अधिकार में जानकारी देने के नाम पर वो किसी हद तक गिरकर आरोप लगाने से बाज नहीं आते फिर ये हरामखोर आवेदक पर ब्लैक मेलिंग का आरोप लगाने से पहले अपने ब्लैक, कुकर्मों और भ्रष्टाचार पर लगाम क्यों नहीं लगाते। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव अभियंता को दी गई पर सभी भ्रष्टाचार में हिस्सेदार होते हैं। किसी ने भी कुछ भी नहीं किया।

फैला रहा नग्नता, बदमीजियां और गंदगी

पेज 8 का शेष

फेसबुक में ऐसे कोई अवसर या साधन उपलब्ध नहीं करवाये गये हैं। ताकि आप ऐसे लोगों को अपनी सूची से बाहर कर सकें, यह सब प्रस्तुति का उद्देश्य है, कि ये आभासी दुनिया की चकाचौंध के पीछे का सच कितना घिनौना हैं। जैसा कि फैशन की दुनिया और फिल्मी दुनिया के पीछे का घिनौना सच, जिसे फिल्मों में नायिका बनाकर प्रस्तुत किया जाता है उसे नायिका बनने से पूर्व वेश्यावृत्ति करने और संचालक से वित्त व्यवस्था करने वाले से लेकर लाइट बाय तक किस-किस को अपना अंग प्रदर्शित करना होता है। ये युवा पीढ़ी नहीं जानती उसे तो पर्दे पर उसकी आदर्श नायिका दिखती है। जबकि वास्तविक जीवन में तो कितनी बड़ी वेश्याओं की भूमिका में जीती है। कितने माफियाओं, गुंडे बदमाशों के साथ सहचर्य करना होता है। यह तो नायिका ही बता सकती है। यही हाल फेसबुक के संचालकों का भी है। कि वे पैसा कमाने के लिये कितने-कितने कहां-कहां कैसे हथकंडे अपने खाताधारकों को खुश करने के लिये अपनाते हैं। कैसे आपके खाते में हर वक्त 5-10 प्रशंसकों और फालोवर्स की सूची चिपक जाती है, कहां से किसको घेर कर लाया जाता है। जो वास्तविकता में आपके जान पहचान वाले होते हैं। उनसे आपक मुश्किल से विचार विनिमय होता है, अनजाने लोगों की भीड़ कैसे आपके पेज पर चिपकी या चिपकाई जाती रहती है। वही हाल टविटर का भी है। उसकी सीमा 140 शब्दों की है। इसलिए वहां आपके विचारों को अत्यधिक संघनित करना पड़ता है। पर उस पर भी अमिताभ बच्चन जैसे लोग अश्लीलता की हदें लांघते हुए लिखते हैं चोली बड़ी या चड्डी, बेशक चड्डी बढ़ी है, जहां से दुनिया बाहर आई है।

अर्थात विचारों को प्रगट करने के ये माध्यम फेसबुक और टवीटर वृहत पैमाने पर अश्लीलता फैलाकर युवा पीढ़ी को जरूर दिग्भ्रमित कर रहे हैं। महिलायें इन माध्यमों से अपनी यौन कुंठायें, स्वतंत्र यौनाचार की भावनायें जरूर पोषित कर पा रही हैं। जो सामाजिक परंपरागत ताना-बाना जो भविष्य के बच्चों के लालन-पालन के लिये आवश्यक है खंड-खंड बिखेर रहा है।

साप्ताहिक समय माया

फेसबुक के जालसाज कमाई के लिये सब कुछ करते हैं

फैला रहा नग्नता, बदमीजियां और गंदगी

चाहकर भी पेज से नहीं हटाते, विज्ञापन, उल्टे सीधे संदेश

पूरे विश्व में टवीट्र और फेसबुक पर करोड़ों बच्चों से बुजुर्ग तक अपने विचारों का आदान-प्रदान करने का वर्तमान में एक विश्वव्यापी माध्यम बन चुका है। बेशक सशक्त माध्यम हैं, दूसरी तरफ फेसबुक के संचालक सभी फेसबुक पर अपने खाते और पेज धारकों के साथ भारी छल-कपट जालसाजियां भी कर अपनी आय को बढ़ाने के साधनों को विज्ञापनों के माध्यम से, अश्लील बातों, विचारों, नग्न एकल, संभोगरत चित्रों को तीव्रता से दूसरों के खातों पर चिपकाकर युवा, बाल्य, मध्य आयु से लेकर प्रौढ़ और बुजुर्गों को भी उनके पेजों पर चिपका कर ध्यानाकर्षण और प्रचार-प्रसारण का कार्य संपन्न करते रहे हैं।

फेसबुक के संचालक पूरे विश्व में अपनी कमाई के लिये पूरा प्रबंधन ही जालसाजी पूर्ण तरीके से करते हैं। जानबूझकर जब भी कोई ख्याति प्राप्त व्यक्ति महिला या पुरुष फेसबुक पर अपना खाता खोलता है, उसके प्रोफाइल को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर उसके खाते से अन्य खाताधारियों को सीधे बात करने का निमंत्रण देकर, लाखों खाताधारियों के खाते पर उसका विवरण भेजकर दोस्ती करने के लिये उकसाया जाता है, इस बीच कं. अपने विज्ञापन करोड़ों रु. में डालकर सीधे ही उत्पाद खरीदने के लिये कहा जाता है, उसकी प्रोफाइल बढ़ा-चढ़ाकर पेश की जाती है, उससे लाखों रु. लेकर उसके लाखों प्रशंसक खड़े किये जाते हैं। जबकि उन ख्यात नाम लोगों को अपने कार्यों से ही इतनी फुर्सत ही नहीं होती कि ट्वीटर या फेसबुक को खोलकर उसमें टवीट कर सकें या फेसबुक पर अपनी प्रोफाइल लोड कर सकें।

कंम्प्यूटर की दुनिया आभासी दुनिया है, इसमें अधिकांश पूरा खेल आभासी आयमों पर चलता है। कंम्प्यूटर के बाद इंटरनेट ने भारी क्रांतियां की हैं इसमें कोई संदेह नहीं, फिर इंटरनेट के चलने में आने के बाद ईमेल, चेटिंग, विडियो कालिंग और टवीट्र, फेसबुक, ब्लॉग जैसी साइटों के आने से मंच, विचार, विनिमय

आदि आभासी मंच क्षेत्रीयता से उठकर, प्रादेशिक और राष्ट्रीयता से उठकर अंतरराष्ट्रीय हो गया और महाद्वीपों की दूरियां सिमटकर कम्प्यूटर की स्कीन पर आ गई, अब कम्प्यूटर की स्क्रीन केवल इलेक्ट्रानिक दृश्य पटल न होकर विश्व की जानकारियों को विनिमय का पलक झपकते ही माध्यम बन गया, यह माध्यम जितना सामाजिक, आर्थिक, वैश्विक स्तर पर लाभकारी है उतना ही सामाजिक, आर्थिक और वैश्विक स्तर पर घोर कष्टकारी और नकरात्मक प्रभात वाला भी है। दूसरा इसके संस्थापक और संचालकों की वास्तविकता में सामाजिक और आर्थिक बदलाव की नियत नहीं उनका उद्देश्य विश्व स्तर कमाई करना है, इसके लिये फेसबुक पर भारी जालसाजियां की जाती हैं। जानबूझकर नग्न चित्रावली और उस पर टिप्पणीयां करवाने के लिये उकसाया जाता हैं, कोई सार्वजनिक छवि वाला व्यक्ति उस पर अपना खाता खोलता है, तो घंटे भर में लाखों प्रशंसक उसकी प्रोफाइल में जोड़ दिये जाते हैं। गैर सार्वजनिक व सामान्य छवि वाले को एक दिन में 5 से ज्यादा को जोड़ने नहीं दिया जाता हैं, जिसके लिये खाताधारी मना करता है, ऐसे चित्र, ऐसे लोगों की टिप्पणियां वहां लगाई जाती हैं। वास्तविक प्रशंसकों को उसके पृष्ठ पर नहीं जाने दिया जाता है। ढेरों विज्ञापन चिपका कर उन्हें खरीदी करने के लिये बार-बार अलग-अलग तरीके से उनकी जानकारियां खाते पर भेजी जाती है। अच्छी बातों के लिये पैसे मांग कर ही उसे प्रोत्साहित किया जाता है। न देने पर उस विचार के या लेख के आगे ढेर सारी टिप्पणियां लिखकर उसे दबा दिया जाता है। फेसबुक के आप्रेटर्स ऐसे जालसाजों की फौज बैठायी गई है। जो आपके खाते में भी उल्टे-सीधे अनचाहे व्यक्तियों की टिप्पणियों को पढ़ने के लिये और अन्य लोगों को आपकी निकृष्ट मानसिकता को प्रगट न चाहकर भी प्रगट करती है।

समय माया के फेसबुक खाते में हजारों अच्छे लोग हैं। पर ज्योति शर्मा, किरण तलकर अपनी बेहूदा टिप्पणियों और नग्न चित्रावली से भरकर रख देती है उनका खाता बंद करने की अनेकों कोशिशें नाकाम रही हैं। उन पर मुस्लिम खाताधारियों की टिप्पणियां जो भारी अश्लील होती हैं का भी खाता अपने खाते से हटाने की कोशिशें नाकाम रही हैं। जबकि दूसरे बुद्धिजीवियों जिसमें अरुण गर्ग, हिन्दू महासभा के शुक्ला चाहकर भी राष्ट्रीयता पूर्ण टिप्पणी करने, विचारों के लेख नहीं भेज पाते,

(शेष पेज 5 पर)

24 घंटे टीवी, इंटरनेट, मोबाइलों पर यौनाचार दृष्य उपलब्ध है

खाप, सर्वोच्च न्यायालय सभी 16 की उम्र में विवाह के पक्ष में

जनता ने संसद व सांसद बनाए हैं, सांसदों को यर्थाथ पर मनन चाहिए

लोकतंत्र में जनता अपने मध्य से सत्ता संचालन के लिए पंच, सरपंच, पार्षद, विधायक और सांसद चुनते हैं। चुने हुए प्रतिनिधियों का दायित्व हैं कि भूत से इतिहास समझें वर्तमान परिस्थितियों का आंकलन कर जनता के सम्पूर्ण विकास और श्रेष्ठ जीवन जनता को मिले इसके लिए भविष्य का नीति निर्धारण करें, इसके विपरीत हमारे सांसद और सत्ता आजादी के 65 वर्ष बाद भी, विदेशी बहुराष्ट्रीय कं. के इशारे पर नाचते हैं। जैसा वे इन्हें सुझाते हैं, ये उसका गुलामों का हर पालन करते हैं। जबकि यूरोप पूरा ठंडा महाद्वीप है, जबकि दक्षिण एशिया पूरा गर्म है। जहां स्त्रीयों का मासिक 12-14 वर्ष की उम्र में शुरू होता है, वहीं लंका में 10-12 की उम्र में ही शुरू हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार स्त्रीयों की रजरगात प्रारंभ होने की उम्र में ही विवाह हो जाना चाहिए, जो शारीरिक आवश्यकता है। अब यदि इस उम्र में विवाह नहीं किया जाएगा तो स्वभाविक है कि फिर स्त्रियों और लड़कियों को घर से भागना ही पड़ेगा।

दूसरी ओर यदि भारतीय मनीषियों ने 14-16 वर्ष की उम्र में विवाह योग्य उम्र बताया था तो वे कहां गलत थे। जैसी वायुमंडलीय परिस्थितियां थी, वैसा ही उन्होंने निर्धारण किया। पर हमारे देश का गुलामी का इतिहास सहस्त्रों वर्ष पुराना है और आजादी के 65 वर्ष ही हुए हैं। हम अपने इतिहास की जड़े कैसे छोड़ सकते हैं। फिर हमारी गुलाम मानसिकता यूरोप की 300 वर्ष की गुलामी और उनके आदेशों के पालन को कैसे त्याग

सकती है, जबकि अब प्रचार-प्रसार माध्यमों की तीव्रता युवाओं को 24 घंटे ही यौनाचार परोस रही है, जिसे देखने-सुनने के लिए उन्हें घर से कहीं बाहर नहीं जाना है। 24 घंटे घरों में चलते टीवी, इंटरनेट और मोबाइल फोनों पर नग्न दृष्या बलियां चल चित्र उपलब्ध है तो आखिर तक रसास्वादन की इच्छाएं युवाओं में जागृत नहीं होगी। हालात इससे भी बदतर ये हैं कि स्कूलों में बैठकर सहशिक्षा में 10-12 वर्ष की उम्र में ही जितना मां-बाप जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है, वे नहीं जानते उतना उनके अपने सहपाठियों के साथ बैठकर स्कूल में मल्टीमीडिया मोबाइल फोनों पर खुलकर यौनाचार के चल चित्र का आनंद लेते हैं। जब सांसद, सरकार की इतनी औकात नहीं कि तो 24 घंटे टीवी, इंटरनेट, मल्टीमीडिया मोबाइल फोनों पर बंट रहे स्वच्छंद यौनाचार को रोक सके, जब यह 24 घंटे युवाओं को उत्तेजक दिखाई जाती है तो फिर विवाह की आयु 18 और 21 वर्ष पर क्यों कानून बना रखा है। जब हमारे मनीषियों ने ही 14-16 वर्ष की आयु निर्धारित कर दी थी तो फिर हरियाणा की खाप पंचायतों द्वारा 16 वर्षों की आयु और मल्टीमीडिया मोबाइल फोनों पर प्रतिबंध लगाकर आखिर भषिष्य की समाज को सुधारने का ही तो प्रयास किया गया। इस संबंध में गाहे-बगाहे मंचों से अगर कोई मंत्री या जानी-मानी शाख्सियत कोई सच बोल ही देती है, तो क्यों ये महिला संगठन उसके विरुद्ध तूफान खड़ा कर देते हैं। जबकि वहीं महिला संगठन के पदाधिकारी महिलाएं यह क्यों नहीं सोचती कि वे जहां खड़ी है। उनकी मां या उनकी बेटी के साथ भी वही गुजरता या गुजरेगा तब ये बयां करेगी तब फिर ये यही कहेगी जो खाप पंचायतों के बुजुर्ग कह रहे हैं। बुजुर्ग महिलाएं इस यर्थाथ को अच्छी तरह से जानती है। इसलिए तो लड़की की 16 वर्ष की उम्र होते ही यथायोग्य वर की तलाश में लग जाती है।

यह अलग तथ्य है कि अब पढ़ने-लिखने और नौकरी करने के कारण वैसे भी भारत में भी लड़कियां सारे यौनाचार को स्कूलों-कॉलेजों में भोगने के बाद, जब निराशा छाने लगती है तो अपनी जीवन साथी के रूप में ऐसे पालतू की तलाश करती है जो उनके इशारों पर नृत्य करता रहे। यह स्थिति अब अधिकांश समाजों की होने लगी है।

पढ़ने-लिखने और नौकरी करने वाली स्त्रीयों में अब बिना शादी के मनचाहे पुरुष के साथ दिल उबने तक जिन्दगी गुजारने में ज्यादा विश्वास करती हैं। शादी के बंधन में बंधकर जीवन गुजारने से अब पुरुषों की अपेक्षा स्त्रीयों को ज्यादा परहेज करने लगती है। यह स्वतछंद चारिता दीपकाल में समाज में भारी विखंडन पैदा करेगा।

त्योहारों पर बिक्री में छूट में, फंसे न लूट में

विज्ञापनों में फंसने से पूर्व जाने समझें, घटी दरें

भारत में दीपावली के त्योहार पर, पूरे दुनिया के उत्पादक जानते हैं कि कचरा, पुराना, समय बाधित, माल भी भारी आकर्षक विज्ञापनों से छूट, घटी दरों पर ग्राहकों को आकर्षित कर बेंच दिया जाता है। बाद में खरीददार घर ले जाकर ठगे जाने का अहसास करता है।

आकर्षक विज्ञापनों को पढ़ने के बाद सबसे ग्राहकों को जो माल खरीदना है, उसकी बिक्री करने वाले दुकानदार, कं. आदि की विश्वसनीयता के बारे में जो उस माल का उपयोग करते हैं। उनसे वास्तविकता के बारे में भली भांति जान सकते हैं। त्योहारों के मौके पर हर उत्पादक और विक्रेता अपना मृतस्कंध, पुराना, चलन से बाहर, दोषपूर्ण, माल भी आसानी से छूट, आधी या चौथाई कीमत का वास्ता देकर बेच देता है। गारंटी और वारंटी के मतलब को समझें, गारंटी और वारंटी की शर्तों की वास्तविकता उनके गूढ़ शब्दों को अपनी चलन की भाषा में समझें, छूट घटी दरों की वास्तविकता और शर्तों को समझें चाहे आप भवन, वाहन, आभूषण, वस्त्र, बर्तनों से लेकर जूते-चप्पल कुछ भी नगद में, उधार में, किश्तों से खरीद रहे हो क्योंकि विक्रेता उत्पादक अपनी जेब से कुछ भी नहीं दे रहा है। वह नगद बेच रहा है तो नगद की छूट के बारे में बात करें और नगद की छूट का लाभ लें। यदि आप किश्तों में ले रहे हैं तो वास्तविक नगद की कीमत और कुल चुकाई जाने वाली राशि की कुल किश्तों की रकम, फाइल बनाने का शुल्क, पंजीयन बीमा राशि आदि

हर कुंजड़ा भी सड़ी सब्जी को भी फेंकने से पहले बेचना चाहता है आधी कीमत में या मुफ्त में भी

की वास्तविकता को बारीकी से समझें और कुल ब्याज की दर, साधारण या चक्रवृद्धि ब्याज की वास्तविकता को समझें, जो चेक आप दे रहे हो, उसमें अग्रिम तारीख के चेकों में धन और तारीखें अवश्य लिखें, कभी इन जालसाजों को बिना तारीख और बिना रकम के खाली चेक कदापि न दें। चाहे विक्रेता माल बेंचे न बेचे क्योंकि तभी आपको माल खरीदने की आवश्यकता है, उतनी ही विक्रेता को माल बेंचकर लाभ कमाने की आवश्यकता है। आप अपनी शर्तों पर ही किश्तों में माल खरीदिए। यदि विक्रेता आपकी कुछ शर्तों को मानने को तैयार नहीं हो उसी माल के दूसरे विक्रेता से माल खरीदिए। यह आप मान कर चलिए कि आप ग्राहक हैं या खरीददार हैं। आप को छोटेसे छोटे या बड़ा पेन, पेंसिल, बिस्कुट खरीदने से लेकर लाखों का मकान, प्लाट, कार, दो पहिया वाहन तक कुछ भी खरीदने से पहले माल की गुणवत्ता, विक्रेता की गुणवत्ता जानने पर रखने, सौदेबाजी करने उसकी गर्मित और स्पष्ट शर्तें भविष्य रख रखाव, गारंटी-वारंटी किस हिस्से या खंड, कल पुर्जे आदि की दी जा रही है। जैसे वर्तमान में भारत में फ्रिज किसी भी नाम का नाम हो, सब पर कब्जा वीडियोकॉन का है, जो कि मात्र 7 वर्ष की कंप्रेसर और उसकी गैस की गारंटी देता है। बाकी दरवाजा टूटने, बाडी सड़ने, वाल फ्यूज, होने व अन्य किसी दोष के लिए 1 वर्ष के बाद 10 से 20 गुना कीमत वसूल कर सुधारते हैं। कम्पनी का मिस्त्री आएगा तो हर बार 20 रुपए वसूलेगा। सुधार खर्च अलग से यही कहानी बजाज के दो पहिया वाहनों में, मारूति की बड़ी गाड़ियों में भी लागू होती है। इंजन की वारंटी के समय में भले ही कुछ धन न हो परन्तु इसके कलपुर्जे 5 वर्ष में ही माल की कीमत से ज्यादा सुधराई और रख रखाव में ही लग जाते हैं। स्वर्ण भूषणों के बाजार को वो डकैतों का ही बराबर कहा जा सकता है बात करेंगे 23 टंच की 92 प्रतिशत खरे सोने की और माल नहीं होगा।

(शेष पेज 5 पर)

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक- अजमेरा एस.पी. कुमार द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13 प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 299, अम्बेडकर नगर, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित।
भोपाल प्रतिनिधि- एस.के. भारद्वाज मो. 9074551045, इंदौर कार्यालय- 0731-2530859, मोबा. 9300755803